20 मार्च, 2020 * वर्ष-29, पृष्ठ संख्या 60, अंक-3

राजस्थान सुजस

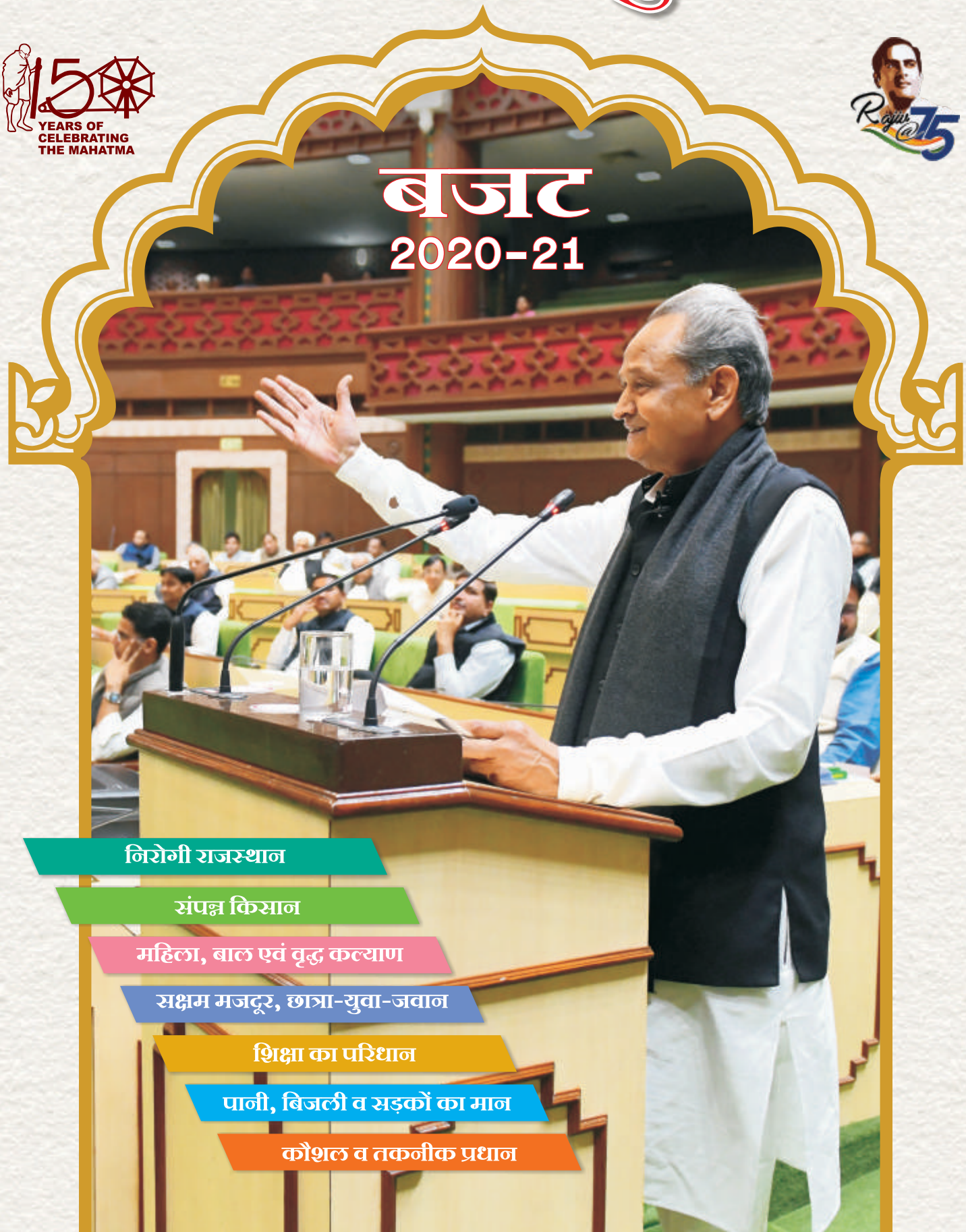

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Rajiv@75

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

बजट 2020-21

को अंतिम रुप देते हुए

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्त वर्ष 2020-21 के राज्य बजट को अन्तिम रूप देते हुए इस पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, शासन सचिव वित्त (बजट) श्री हेमन्त गेरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज, विशिष्ट सचिव वित्त (व्यय) श्री सुधीर शर्मा एवं निदेशक बजट श्री शरद मेहरा उपस्थित थे।

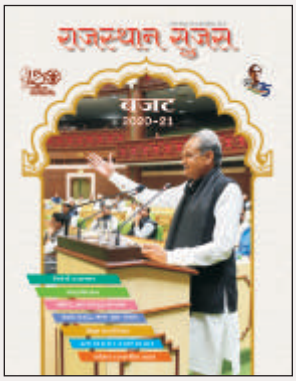

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

सम्पादक
डॉ. राजेश कुमार व्यास

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 29 अंक : 03 **मार्च, 2020**

इस अंक में

कोरोना से बचाव...

06

राजस्थान की स्थापना...

16

बजट - 2020-21

32

सम्पादकीय	04
घबरायें नही, सावधानी बरतें...	05
कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा	08
औषधि नियंत्रण संगठन...	10
घर-घर पहुंचेगा निरोगी राजस्थान का संकल्प	11
उद्योगों के हित में है राज्य सरकार की नीतियां	11
कल्याणकारी बजट घोषणाओं के लिए...	12
मुख्यमंत्री बोले, वागड़ क्षेत्र से है पुराना रिश्ता ...	12
मेक इंडिया वाटर समिट-2020...	13
रिक्त पदों पर जल्द हो नियुक्तियां	13
सिलिकोसिस बीमारी की प्रभावी रोकथाम...	14
मुख्यमंत्री से मिले कराटे प्रतियोगिता...	14
रिफाइनरी के साथ ही नए तेल अन्वेषण कार्यों...	15
गांधी दर्शन के संकल्प का समावेशी बजट	20
सात संकल्पों का सर्वकल्याणकारी बजट	22
बुल्गा, बोऊगेट, बोगेट शब्दों के सफर...	24
सफरनामा	24
बजट : पर्यटन एवं आयुर्वेद	30

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

निरोगी राजस्थान...

10

युवा उम्मीदों को पूरा करने...

28

भंवर म्हाने खेलण दो गणगौर

57

सर्वांगीण विकास का सर्वकल्याणकारी बजट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा विधानसभा में वर्ष 2020-21 का प्रस्तुत बजट इस मायने में बेहद महत्त्वपूर्ण है कि इसमें सभी वर्गों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुये प्रावधान किये गये हैं। कह सकते हैं सर्वांगीण विकास का यह सर्वकल्याणकारी बजट है। बजट में इस बार मुख्यमंत्री जी ने सात संकल्पों पर जोर दिया है। निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़कों का मान तथा कौशल व तकनीक प्रधान-इन सात संकल्पों के आईने में देखें तो यह ऐतिहासिक बजट है। इसमें सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को तेजी से विकास की राह पर ले जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने रखा है।

बजट वर्ष भर के कार्यों का आय-व्ययक होता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इसमें सुनियोजित सोच के साथ विभागवार बजट प्रावधान किए हैं। इस बार के बजट में निरोगी राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभागों के लिए 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपये, कृषि विभाग के लिए 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सहकारिता के अंतर्गत 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1800 करोड़ रुपये के फसली ऋण प्रदान करने की घोषणा की गयी है।

शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान प्रसार हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा के क्षेत्र में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पेयजल के लिए 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख, विद्युत विभाग के लिए 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपये, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 808 करोड़ 63 लाख रुपये तथा जल संसाधन विभाग के लिए 4 हजार 557 करोड़ 87 लाख रुपये राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रस्तुत इस बार का बजट इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी को केन्द्र में रखते हुए स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड़ के फण्ड, 'राजीव गाँधी ग्रामीण आईटी हब-राजगृह' के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को और मजबूती प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। बजट में राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेलों के आयोजन हेतु जहां विशेष प्रावधान किये गये हैं वहीं जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के 'राजस्थान अन्तरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो' के आयोजन, जयपुर में 'खादी प्लाजा' की स्थापना, युवाओं में कौशल विकास हेतु विशेष कार्यक्रम, निजी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का अनिवार्य उपचार, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना आदि की पहल की गयी है। स्पष्ट ही है कि बजट में सुनियोजित सोच के तहत आम जन के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है।

कोरोना महामारी से निपटने में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सुरक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए प्रारम्भ से ही युद्धस्तर पर जागरूकता अभियान चलाते हुए प्रभावी मोनिटरिंग की जा रही है। इसी का सुपरिणाम है कि राजस्थान में स्थिति अभी तक नियंत्रण में है। अन्य देशों के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि यदि हमने भीड़, मेलों, शादी-विवाह, धार्मिक स्थलों पर एकत्रित होने पर आगामी कुछ सप्ताह के लिए स्वप्रेरणा से रोक नहीं लगाई तो स्थिति भयावह हो सकती है। बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है- सामाजिक व्यवहार (मेल-मिलाप) या भीड़ से कुछ सप्ताह तक बचें क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह इस महामारी के फैलाव का खतरनाक चरण है। राज्य सरकार के प्रयास व आप सभी के संकल्प से हम इस पर निश्चित ही विजय प्राप्त कर सकेंगे।

महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

घबरायें नही, सावधानी बरतें, लोगों को जागरूक करें और कोरोना को मात दें

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस को फैलाव से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे घबरायें नहीं। सावधानी बरतें। हाथ ना मिलायें। नमस्ते करें। राज्यपाल ने कहा कि जुकाम, खांसी की स्थिति में तत्काल राजकीय चिकित्सालय को सूचित करें। श्री मिश्र ने कहा कि ऐसे प्रयास किये जाये कि एक स्थान पर अधिक भीड़ न हो।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार व मेडिकल टीम द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था की जा रही है, उसी प्रकार इस कार्य की नियमित रूप से मॉनिटिरिंग की जाने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्य में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि सावधानी बरती गई तो निश्चित रूप से राजस्थान कोरोना वायरस को मात दे देगा। राज्यपाल ने निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को प्रभावी रूप से लगातार जारी रखने के लिए कहा है।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भी कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के कार्यक्रम चलाये जायें। आसपास के क्षेत्र के लोगों में जागरूकता लाने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयास किये जायें। राज्यपाल ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाना ही इस रोग से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से इस वायरस के विस्तार को रोका जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि एयरपोर्ट और राज्य के प्रत्येक जिले में लोगों की स्क्रीनिंग की मजबूत व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए शिक्षा संस्थानों में अवकाश रखने के साथ परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जावे।

राज्यपाल श्री मिश्र ने राजभवन में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उपायों की एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि प्रत्येक जिले में आइसोलेशन वार्ड की पर्याप्त व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये और मेडिकल स्टाफ को किट उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण न फैले, इसके लिए सेनेटाइजेशन कराया जावे। राज्यपाल श्री मिश्र को मुख्य सचिव श्री डी.बी.गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में अब तक तीन व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है जिनमें दो नागरिक विदेशी हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में डिजास्टर मैनजमेन्ट एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कराया जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु समस्त जिलो में कार्यरत आशा सहयोगिनी, एएनएम, जिला ब्लॉक एवं सेक्टर स्तर के समस्त सुपरवाइजरी स्टाफ को कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्यपाल को श्री सिंह ने बताया कि महा प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेल्वे को भी इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंदिरों के प्रबंधक को भी संक्रमण रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। यह भी निर्देशित किया है कि वे मंदिर परिसर के फर्श, रैलिंग, दरवाजे, खिड़कियों एवं बैंचेज को एक प्रतिशत सोडियम हाइपर क्लोराइड सॉल्यूशन के माध्यम से भी विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित करें और मंदिर परिसरों में आईईसी के माध्यम से लोगों को जागरूक करे।

बैठक में बताया गया कि समस्त राज्य के स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अग्रिम आदेशों तक सभी राजपत्रित अवकाशों पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं अनुपस्थित रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। राज्य के विभिन्न विभाग यथा - राजस्थान राज्य परिवहन निगम, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को विभिन्न पत्रों के माध्यम से कोरोना वायरस के विसंक्रमण हेतु समुचित उपाय करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कन्टामिनेन्ट प्लान को भी राज्य में अक्षरशः लागू किया जा रहा है। •

कोरोना से बचाव के लिए सर्वदलीय एवं सर्वसमाज की बैठक

कोरोना से बचाव के लिए अगले दो सप्ताह महत्त्वपूर्ण; सामाजिक व्यवहार और भीड़ से बचें लोग

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी धर्मगुरुओं, विभिन्न समुदाय एवं समाजों के प्रतिनिधियों तथा सभी विपक्षी दलों के नेताओं से प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्य सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस महामारी के संक्रमण को सीमित कर लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। फिलहाल प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन अगले 2-3 सप्ताह तक लोगों को भीड़भाड़ से दूर रखना बेहद जरूरी है।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्व दलों के नेताओं और धर्मगुरुओं तथा विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में कहा कि यदि प्रदेश की जनता अगले 15-20 दिन तक सामाजिक व्यवहार कम रखेगी और भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचेगी तो हम इस बीमारी से जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए कफ्र्यू नहीं लगाएगी, लेकिन लोगों को स्वयं सा व्यवहार करना होगा जैसे कि कर्फ्यू लगा है। किसी धार्मिक स्थल पर ताला नहीं लगे, लेकिन धर्मगुरु और समाजों के पदाधिकारी सा माहौल बनाएं कि श्रद्धालु स्वयं धर्मस्थलों पर नहीं आएं।

धर्मगुरुओं ने जारी की संयुक्त अपील

मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विभिन्न सम्प्रदायों के धर्म गुरुओं और प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त अपील जारी की, जिसमें प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए 31 मार्च तक धार्मिक स्थलों पर एकत्र न होने और यथासम्भव अपने घर पर ही ईश्वर की प्रार्थना करने का संदेश दिया गया है। अपील में कहा गया है कि देश के कई धार्मिक स्थलों पर संबंधित ट्रस्टों ने पहल करके श्रद्धालुओं के धर्म स्थल पर आने पर पाबंदी लगा दी है। आमजन की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं।

अगले दो-तीन सप्ताह विशेष रूप से महतत्त्वपूर्ण

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक हरसम्भव प्रयास किए हैं, जो सफल भी रहे हैं। अब आमजन की जिम्मेदारी है कि वे महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सजग रहकर इस चुनौती से निपटने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के अनुभव से पता चला है कि वायरस के संक्रमण के गुणात्मक फैलाव को रोकने के लिए अगले दो-तीन सप्ताह प्रदेश के विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होंगे।

धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि यह विपत्ति का समय है, इसका सामना करने के लिए सभी को राज्य सरकार की पहल में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं 4करना चाहती, लेकिन आम आदमी का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग एकजुट होकर संक्रमण को रोकने का प्रयास करें। संक्रमण का रोकथाम ही इस बीमारी से सर्वोत्तम बचाव है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बड़े रूप में जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।

सरकार के दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित करेंगे

धर्मगुरूओं ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार और चिकित्सकों द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि विभिन्न धर्मस्थलों पर स्वप्रेरणा से इस संक्रमण से बचाव के लिए कदम उठाए गए हैं। आगे भी सरकार जो भी एडवाइजरी तथा दिशा-निर्देश जारी करेगी, उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी।

सभी राजनीतिक दल करें सरकार का सहयोग

मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि कोरोना बीमारी पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का इस आपदा से निपटने में सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी दल अपने-अपने संगठन के माध्यम से गांव-ढाणी तक इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब राज्य सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दे सकते हैं।

सरकार के प्रयासों को सराहा

बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि हम सरकार के प्रयासों में हर कदम पर साथ हैं। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज द्वारा इस बीमारी के लिए ईजाद की गई दवा एवं अन्य प्रयासों के लिए चिकित्सकों की सराहना की। सीपीएम के विधायक श्री बलवान पूनिया, सीपीएम के ही डॉ. संजय माधव, सीपीआई के श्री डीके छंगाणी, श्रीमती सुमित्रा चौपड़ा, आम आदमी पार्टी के रामपाल जाट, भाकपा के श्री नरेन्द्र आचार्य सहित अन्य नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को जनता तक पहुंचाने में पूर्ण सहयोग करने की बात कही।

अब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, आपात योजना भी तैयार

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने बैठकों में बताया कि प्रदेश में केन्द्र सरकार की ओर से प्राप्त गाइड लाइन के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए सभी सम्भव उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, जिसके चलते अब तक हर संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने और लगातार मॉनीटरिंग करने में सफल रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है तथा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली गई है।

एसएमएस के प्रोटोकॉल को दी विशेषज्ञों ने मान्यता

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी ने बताया कि संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए हमारे पास उच्चस्तरीय वाइरोलॉजी लैब और चौबीस घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए एसएमएस में तैयार प्रोटोकॉल को मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया के साथ विभिन्न देशों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मान्यता दी है।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क श्री महेन्द्र सोनी, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गाँव–गाँव ढाणी–ढाणी, तक होगा व्यापक प्रचार–प्रसार

इससे पहले चिकित्सा तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा न्यूज चैनल्स, रेडियो सहित अन्य माध्यमों से लगातार प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रदेशभर के अस्पतालों सहित विभिन्न स्थानों पर कोरोना की जानकारी से सम्बन्धित होर्डिंग्स लगाएं जाए। एसएमएस एवं टोल फ्री नम्बर से लोगों को संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए। गांव-ढाणी तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

धर्मगुरुओं द्वारा जारी संयुक्त अपील

जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस , ईरान सहित कई देशों में इस वायरस का संक्रमण विकराल रूप ले चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी और अमेरिका जैसे देश ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। विभिन्न देशों में इस बीमारी के अनुभव से पता चला है कि इस वायरस का संक्रमण 2-3 सप्ताह बाद अचानक बढ़ता है और फिर संक्रमित लोगों और इससे होने वाली मौतों की संख्या एकदम बढ़ जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी से बचने का सर्वोत्तम उपाय है लोग भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। आपसी मेल-मिलाप और सामाजिक व्यवहार कम से कम हो।

इसे देखते हुए सभी विद्यालय, कॉलेज, जिम्नेजियम, स्मारक, सिनेमा हॉल आदि बंद किए जा चुके हैं। 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

महाराष्ट्र के मुम्बादेवी, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, शिरड़ी साईं मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर आदि धार्मिक स्थलों पर सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा स्वयं पहल करके श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य में कई मेले, त्यौहार आदि भी आयोजित हो रहे हैं, जिनमें काफी भीड़ रहती है। इस रोग के अचानक गुणात्मक रूप से फैलने के खतरे को देखते हुए यह आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नहीं आएं ताकि आमजन के जीवन की सुरक्षा हो सके।

राजस्थान में राज्य सरकार के प्रयासों से अभी तक इस वायरस के संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में हैं। हमारा प्रदेश इस महामारी से बचा रहे और हम सब स्वस्थ रहें, इसके लिए सभी श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों से अपील है कि वे फिलहाल 31 मार्च तक धार्मिक स्थलों पर एकत्र होने से बचें। यथासम्भव सब अपने घर पर ही ईश्वर की प्रार्थना करें। •

कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए। इस अवधि में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क तथा नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे।

श्री गहलोत ने देर रात्रि मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में ऐहतियात के तौर पर संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने आमजन को कोरोना के विषय में भयभीत नहीं होने की सलाह दी है और लोगों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें तथा आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें।

श्री गहलोत ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही, मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज में कार्य संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से शादी समारोहों को छोटा रखने तथा सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से एडवाइजरी आदि जारी कर आमजन को जागरूक करें।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए 370 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से केवल 3 ही मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ित मरीजों का इलाज सही दिशा में चल रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में कुल 3 लाख लोगों की कोरोना के संक्रमण की स्क्रीनिंग की गई है।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल,

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ. सुधीर भण्डारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि संक्रमण रोकथाम ही इस बीमारी से सर्वोत्तम बचाव है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बड़े रूप में जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन, इटली, ईरान और अमेरिका में इस बीमारी के अनुभव से यह पता चला है कि शुरूआती दौर में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे-धीरे फैलता रहता है और फिर अचानक संक्रमित लोगों की संख्या और इससे होने वाली मौतों की संख्या एकदम बढ़ जाती है। ऐसे में, कोरोना के संक्रमण को अनियंत्रित होने से रोकना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर लगातार संवेदनशील है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी एतिहाती कदम उठा रही है।

श्री गहलोत ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न देशों में इस बीमारी से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सबक लेते हुए यह आवश्यक है कि लोग भीड़-भाड़ से बचें तथा बहुत अधिक आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्थलों पर जाएं। उन्होंने कहा कि इस क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी पर्यटन स्थलों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक

इमारतों, किलों, सार्वजनिक मेलों, पशु हटवाड़ों, पार्क, खेल मैदानों आदि में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे आमजन की जागरूकता और समझाइश के लिए लगातार एडवाइजरी जारी करें तथा लोगों को भयभीत नहीं होने और लगातार सचेत रहने की सलाह दें। अधिकारियों ने श्री गहलोत को अवगत कराया कि फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और लगातार एतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री नरेश ठकराल, आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क श्री महेन्द्र सोनी, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ. सुधीर भण्डारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। •

निरोगी राजस्थान बनेगा पाठ्यक्रम का हिस्सा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि बुजुर्ग से लेकर प्रदेश का बच्चा-बच्चा स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो, 'निरोगी राजस्थान' अभियान के पीछे सरकार की यही मंशा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री कार्यालय में निरोगी राजस्थान अभियान तथा नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने प्रिवेंटिव हैल्थ का इतना बड़ा कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जो प्रदेशभर के लोगों को फिट रहने और उचित उपचार के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द ही एक निरोगी हेल्पलाइन शुरू की जाए, जिस पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श आसानी से मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करवाएगी, जिससे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध होगी। एएनएम एवं आशा सहयोगिनियों के जरिए किया जाने वाला यह सर्वे प्रदेशवासियों को निरोगी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा। श्री गहलोत ने कहा कि लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाहों, एनजीओ, विधायक कोष आदि के सहयोग से और अधिक जनता क्लिनिक खोले जाएं।

श्री गहलोत ने कहा कि आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए पिछले कार्यकाल में हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। निरोगी राजस्थान के तहत इस अभियान को लगातार चलाया जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति मिलावट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेजों की जल्द स्थापना की समीक्षा करते हुए कहा कि इनके टेंडर, डिजाइन और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर सितम्बर माह से पहले इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू हो जाने से लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री गहलोत ने भरतपुर एवं चूरू के मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल भवन के घटिया निर्माण और अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि दोनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में गड़बड़ियों की विशेषज्ञों से जांच करवाई जाए। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से तैयार होने वाले भवनों में किसी तरह की गड़बड़ी को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। •

औषधि नियंत्रण संगठन के नए भवन का शिलान्यास

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने स्वास्थ्य भवन में 3 करोड़ की लागत से बनने वाले औषधि नियत्रंण संगठन के नए भवन का पत्थर और सीमेंट लगाकर शिलान्यास किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में औषधि नियंत्रण संगठन के लिए भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए करीब 12 करोड रुपए से ज्यादा की राशि व्यय की जाएगी। कहीं नए भवन बनेंगे कहीं भवनों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में इनका कार्य पूरा करवाया जाएगा ताकि औषध नियंत्रण के कार्य को गति मिल सके।

औषधि नियंत्रक डॉ. राजाराम शर्मा ने बताया कि इस निर्माण के बाद राज्य में दवा के उत्पादन, वितरण, विक्रय आदि से संबंधित प्रक्रिया को मुख्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 1018 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में 2 औषधि नियंत्रक, 7 सहायक औषधि नियंत्रक और 9 औषधि नियंत्रण अधिकारी कक्ष बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भवन में मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड, रूम, स्टोर, पेंट्री कक्ष भी बनाए जाएंगे। भवन में करीब 50 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। •

घर-घर पहुंचेगा निरोगी राजस्थान का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्कूली बच्चों को निरोगी राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान का संकल्प घर-घर तक पहुंचाने में भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 11 विभिन्न स्कूलों के इन बच्चों तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि वे आमजन को रोगमुक्त रहने तथा ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे और दुर्लभ बीमारियों से बचाव का संदेश पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में सहभागी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निरोगी राजस्थान, अंगदान तथा रेयर डिजीज से संबंधित जागरूकता पोस्टर एवं फोल्डर का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान के रूप में एक सा अभियान चलाया है जो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोगमुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगा। आशा सहयोगिनियों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित चिकित्सा विभाग की पूरी टीम और ग्राम स्तर पर बनाए जाने वाले स्वास्थ्य मित्रों के माध्यम से इस अभियान को जन आन्दोलन बनाया जाएगा। निशुल्क दवा योजना तथा निशुल्क जांच योजना के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का यह बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। •

उद्योगों के हित में हैं राज्य सरकार की नीतियां

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जबकि पूरा देश इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर चिंतित है, केन्द्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़े। क्रय शक्ति सुधरेगी तभी देश से आर्थिक सुस्ती के वातावरण को दूर करने में मदद मिलेगी। ऐसे चिंताजनक समय में रिप्स-2019, एमएसएमई एक्ट-2019 तथा सोलर एवं विंड एनर्जी सेक्टर को प्रोत्साहन देने वाली राज्य सरकार की नीतियों की पूरे देश में सराहना हुई है तथा सभी ने इनका स्वागत किया है। श्री गहलोत जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से ट्रेड एवं तकनीकी विषय पर आयोजित एग्जीबिशन, कांफ्रेंस एवं अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों एवं फैसलों के माध्यम से वे सभी प्रयास करेगी जिससे उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हम राज्य में से उद्योगों को स्थापित करने के लिए नया एक्ट लेकर आए और पहले तीन साल तक एमएसएमई उद्यमियों को विभिन्न सरकारी मंजूरियों एवं हस्तक्षेप की चिंता से मुक्त किया।

उन्होंने कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए किसानों के

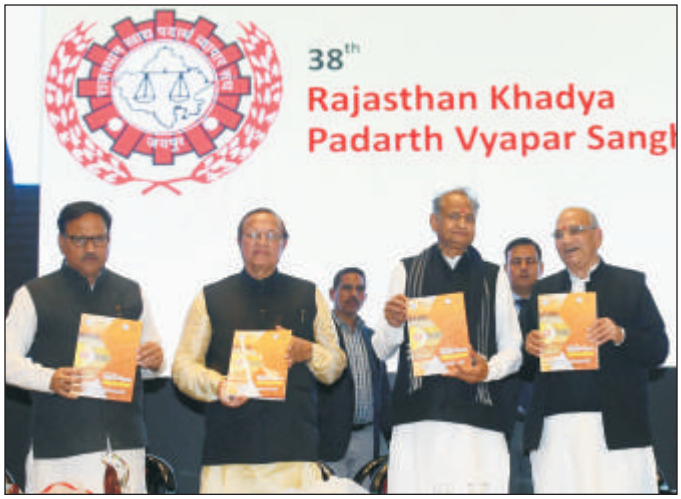

परिजनों को मंडी समिति की ओर से सहायता राशि के चैक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की स्मारिका का विमोचन भी किया। ऊर्जा मंत्री श्री बी डी कल्ला ने कहा कि निरोगी रहने के लिए जरूरी है कि हम सभी सात्विक आहार को अपनाएं। मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने कहा कि निरोगी राजस्थान को साकार करने की दिशा में कारोबारी जगत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। •

कल्याणकारी बजट घोषणाओं के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से खिलाड़ियों, कॉलेज शिक्षकों, होम्योपैथी चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की और राज्य बजट में की गई कल्याणकारी घोषणाओं तथा अन्य फैसलों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में एथलेटिक्स, कबड्डी तथा वूशू के खिलाड़ी इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जितनी घोषणाएं इस बार बजट में की गई हैं, वे अभूतपूर्व हैं।

पूर्व ओलम्पियन धावक श्री गोपाल सैनी तथा कबड्डी कोच श्री हीरानन्द कटारिया सहित अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि ओलम्पिक, एशियन तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर मिलने वाली इनामी राशि को चार गुना तक बढ़ाने, 500 खेल कोच लगाने, खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्ता राशि को दो गुना करने तथा फिट राजस्थान-हिट राजस्थान जैसी घोषणाओं से निश्चय ही प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

बानसूर विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत के साथ बड़ी संख्या में बानसूर से आए लोगों, किसानों, अधिवक्ताओं आदि ने बानसूर में सीनियर सीजे एंड एसीजेएम कोर्ट, नई स्वतंत्र कृषि उपज मंडी तथा नगरपालिका की घोषणा के लिए श्री गहलोत का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि 70 सालों में कभी भी बानसूर क्षेत्र के लिए एक साथ इतनी घोषणाएं नहीं हुई जितनी की इस बार की गई हैं। राजस्थान होम्यो फिजीशियन एवं होम्योपैथिक कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर एवं जोधपुर में राज्य के पहले सरकारी होम्यापैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे होम्योपैथी को प्रोत्साहन मिलेगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. टीपी यादव, डॉ. अजय यादव एवं अन्य होम्यापैथी चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को बुके एवं गुलाब के फूल भेंट कर इस घोषणा का स्वागत किया। •

मुख्यमंत्री बोले, वागड़ क्षेत्र से है पुराना रिश्ता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास हो। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में सी कई घोषणाएं की गई हैं जिनके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।

श्री गहलोत बजट घोषणाओं तथा अन्य फैसलों को लेकर आभार व्यक्त करने आए वागड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वागड़ से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। यहां के लोगों ने जो प्यार एवं आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पूर्व सरकार के समय वागड़ क्षेत्र को बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रतलाम रेल लाइन, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट सहित अन्य सौगातें दी गई थीं लेकिन सरकार बदलने के बाद इन पर काम नहीं हो सका। हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ये योजनाएं आगे बढ़ें। सामान्य वर्ग के युवाओं को आरक्षण का लाभ देने के लिए हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को समाप्त किया। पूरे देश में हमारी सरकार की इस पहल का सकारात्मक संदेश गया है।

प्रतिनिधिमंडल के साथ आए लोगों ने वागड़ क्षेत्र की बजट घोषणाओं के लिए श्री गहलोत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिन के समय दो ब्लॉक में किसानों को विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा से क्षेत्र के काश्तकारों की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई है। योजना के पहले चरण में वागड़ क्षेत्र के जिलों को भी शामिल किया गया है। टीएसपी क्षेत्र के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैसी घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण से सामान्य वर्ग के उन बच्चों को बड़ा फायदा मिला है जो विसंगतियों के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। •

मेक इंडिया वाटर समिट–2020

जल संरक्षण की परम्परा सदियों से

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पानी की समस्या से आज पूरा विश्व चिंतित है। राजस्थान में जल संरक्षण की परम्परा सदियों से रही है। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पहले कार्यकाल में हमने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का संदेश घर-घर तक पहुंचाया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। पानी की समस्या के समाधान के लिए सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा।

श्री गहलोत टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 'मेक इंडिया वाटर समिट-2020' को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान जल संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के कुओं और बावड़ियों सहित अन्य जल स्रोतों पर कई लेख लिखे गए। जल संरक्षण के ये प्रयास हमें पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की और इस दिशा में सार्थक कदम उठाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को जन-जन तक ले जाना जरूरी है। हम जागरूक नहीं होंगे तो जल संकट और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेती में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के उपयोग को और बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्त्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस पर भारी वित्तीय भार को देखते हुए केन्द्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। उन्होंने घर-घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान की विषम भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए इस योजना में भी केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत राशि वहन करे।

मुख्यमंत्री ने देश के वर्तमान आर्थिक हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक मंदी के कारण उद्योग-धंधों, निवेश एवं रोजगार पर विपरीत असर पड़ रहा है। सबको मिलकर इस दिशा में सोचना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके। उन्होंने वाटर समिट के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसमें हुई चर्चा से जल संरक्षण के लिए बेहतर सुझाव मिल सकेंगे।

समिट में हुए पैनल डिस्कशन का सार बताते हुए श्री नितिन भाटी ने कहा कि राजस्थान ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कई उदाहरण पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि समिट में हुई चर्चा में कई अच्छे सुझाव सामने आए हैं जिनका लाभ पूरे देश को मिल सकता है। •

रिक्त पदों पर जल्द हो नियुक्तियां

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के अवसर देने के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ-साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को तत्परता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के लिए कई महीनों तक इंतजार युवाओं के साथ अन्याय है। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्तियों और प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के लिए दूसरी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सभी लम्बित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने तथा मौजूदा रिक्तियों के लिए नए विज्ञापन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी हो, ताकि प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों में देरी नहीं हो। बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 35 हजार 39 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। साथ ही 25 हजार 307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं।

श्री गहलोत की अध्यक्षता में पिछली बार हुई भर्तियों की समीक्षा बैठक के बाद से प्रशासनिक सुधार विभाग में कनिष्ठ सहायक के 12 हजार 456 पदों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 9 हजार 322 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 25 हजार 868 विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा 6 हजार 660 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। •

सिलिकोसिस बीमारी की प्रभावी रोकथाम के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है निर्माण मजदूरों की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए निर्माणकर्ताओं से सेस की प्रभावी वसूली की जाए, ताकि मजदूरों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सिलिकोसिस बीमारी के प्रभावी रोकथाम के लिए निर्माण, खनन तथा मूर्तिकला आदि उद्योगों के लिए एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए।

श्री गहलोत ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगे सभी मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें योजनाओं के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाए। उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक 'वर्किंग ग्रुप' बनाने के निर्देश दिए, जो इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे। मुख्यमंत्री ने मजदूर की दुर्घटना अथवा सामान्य स्थितियों में मृत्यु पर देय लाभ सहित अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को तार्किक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी मजदूर को लाभ से वंचित नहीं किया जाए तथा लाभ वितरण में पूर्ण पारदर्शिता हो। उन्होंने कहा कि निर्माण, खनन तथा मूर्तिकला कारखानों में मालिकों के साथ-साथ मजदूरों को भी सिलिकोसिस से बचाव के साधन अपनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 25 लाख मजदूर भवन एवं अन्य संन्निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य निर्माणकर्ताओं से 1 प्रतिशत की दर से सेस वसूला जाता है, जिससे मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में निर्माणकर्ताओं से वर्तमान में सेस के रूप में वसूले जा रहे 400 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व संग्रहण संभव है। श्री गहलोत ने कहा कि निर्माणकर्ताओं से सेस की प्रभावी वसूली के लिए निर्माणाधीन भवनों की जीआईएस मैपिंग की जाए। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने और वसूली में आईटी के इस्तेमाल से पारदर्शिता रहेगी। उन्होंने निर्माणकर्ताओं को सेस चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी समझाइश करने का भी सुझाव दिया। •

मुख्यमंत्री से मिले कराटे प्रतियोगिता के पदक विजेता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर 25वीं यूरो एशिया ओपन अन्तरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के स्वर्ण एवं रजत पदक विजेता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। श्री गहलोत ने सभी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

श्री गहलोत से मिले पदक विजेताओं में अरूण शर्मा, भानुज डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो एवं माहिर मुलानी तथा उनके कोच दिनेश डाबी शामिल थे। •

रिफाइनरी के साथ ही नए तेल अन्वेषण कार्यों को भी प्राथमिकता

राज्य सरकार बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना के साथ-साथ प्रदेश में नए तेल अन्वेषण कार्यों को भी प्राथमिकता दे रही है। इससे रिफाइनरी में तेल शोधन शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त क्रूड ऑयल उपलब्ध हो सकेगा और प्रदेश के बाहर से तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पचपदरा में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही।

श्री गहलोत ने कहा रिफाइनरी का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बिंदुवार समीक्षा की और कहा कि इस प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों के कार्य तय समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने रिफाइनरी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार पानी एवं बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के निर्माणाधीन कार्यो का अवलोकन भी किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार यहां पेट्रो केमिकल हब की भी स्थापना करने जा रही है, जिसके चलते बड़े क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के निर्माण में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे पेट्रो केमिकल क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकेंगे।

श्री गहलोत ने कहा कि करीब एक चौथाई कार्य प्रगति पर है और करीब 20 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की निविदा जारी की जा चुकी है। अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। वर्तमान में यहाँ 3800 कर्मचारी नियोजित हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नौ मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाली राजस्थान रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और इसके बनने से राज्य का चहुंमुखी विकास होगा। रिफाइनरी का कार्य पूर्ण होने से राज्य की आय में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी निर्माण के दौरान ही स्थानीय स्तर पर बेहतर जनसुविधाओं का विकास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल सीएसआर के अंर्तगत साजियाली गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण समय पर पूर्ण करे तथा रिफाइनरी के पास उच्च स्तरीय स्कूल एवं चिकित्सालय भी बनाए, ताकि स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पचपदरा में एचपीसीएल एवं आरएसएलडीसी द्वारा प्रस्तावित कौशल विकास केंद्र भी शीघ्र शुरू करने को कहा, ताकि

स्थानीय युवा प्रशिक्षण लेकर रिफाइनरी में रोजगार हासिल कर सकें।

बैठक में एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एमके सुराणा ने पावर-प्वाइंट प्रजेन्टेशन के जरिए निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान रिफाइनरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शेखर गायकवाड़ ने क्रूड ऑयल के रिफाइनरी में आने तथा तेल शोधन की प्रक्रिया, रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रो उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, विधायक श्री मदन प्रजापत, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री गोविन्द शर्मा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्री कुंजीलाल मीणा, निदेशक खान श्री गौरव गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। •

राजस्थान की स्थापना

ऐतिहासिक आईने में आय-व्ययक अनुमान (बजट)

– विनोद कुमार मिश्रा

रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान निर्माण के अन्तिम चरण में ही विधान परिषद की स्थापना की प्रक्रिया प्रदेश में प्रारम्भ हो गई थी। यह प्रक्रिया वर्ष 1952 के आरम्भ तक चलती रही। राजस्थान विधान सभा मार्च 1952 में अस्तित्व में आई। पहली विधान सभा की बैठक सवाई मानसिंह टाउन हॉल (पूर्व विधान सभा भवन) में 29 फरवरी 1952 को प्रातः 8.30 बजे प्रारम्भ हुई। विधान सभा में पहली बार 7 अप्रेल 1952 को पहला आय-व्ययक अनुमान तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 20 फरवरी 2020 को दिए गये बजट भाषण को मिलाकर अब तक कुल 78 बजट भाषण विधान सभा में दिये जा चुके हैं। इनमें से 54 भाषण सवाई मानसिंह टाउन हॉल (पूर्व विधान सभा) में दिये गये तथा शेष 24 बजट भाषण इस वर्तमान विधान सभा भवन में दिये गये हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना के साथ ही राजस्थान विधान सभा के गठन और अब तक प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमान (बजट) का सिंहावलोकन कराता यह आलेख विशेष रुप से 'सुजस' के पाठकों के लिए दिया जा रहा है।

– संपादक

मार्च माह में प्रदेश दो अवसरों का साक्षी रहता है। एक तो राजस्थान का स्थापना दिवस और दूसरा राज्य का बजट। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान के गठन के गौरवाशाली इतिहास पर एक नजर डालना प्रासंगिक होगा। राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था जिसमें बाईस छोटी-बड़ी रियासते थीं। यद्यपि 15 अगस्त, 1947 को ही समस्त रियासतें भारतीय संघ से संबंधित घोषित हो चुकी थीं किन्तु भारत में समस्त रियासतों के विलय और इनके एकीकरण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में वर्ष 1947 के माह अप्रेल तक पूरी हुई।

विलय के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर किया गया और इसका उद्घाटन 17 मार्च, 1948 को हुआ। श्री शोभा राम के नेतृत्व में संघ का मंत्रिमंडल गठित किया गया। राजस्थान संघ, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ शाहपुरा, टोंक, कोटा सम्मिलित थे, का उद्घाटन 25 मार्च, 1948 को हुआ। कोटा को इस संघ की राजधानी होने का सौभाग्य मिला। कोटा नरेश को राजप्रमुख पद पर व श्री गोकुल लाल असावा को मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया किन्तु इस उद्घाटन के तीन दिन बाद ही उदयपुर महाराणा ने संघ में सम्मिलित होने

का निर्णय लिया जिसे भारत सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उदयपुर महाराणा को इस राजस्थान संघ का राजप्रमुख व कोटा नरेश को उप राजप्रमुख बनाया गया व श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल का गठन किया गया। इस संघ का उद्घाटन पं. जवाहर लाल नेहरू ने 18 अप्रेल, 1948 को किया। राजस्थान संघ की स्थापना के साथ ही बीकानेर, जैसलमेर जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों के संघ में विलय ओर वृहत्तर राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विधिवत् उद्घाटन किया। जयपुर महाराजा को राज प्रमुख, कोटा नरेश को उप राजप्रमुख के पद का भार सौंपा गया और श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाया गया। मत्स्य संघ का वृहत्तर राजस्थान में 15 मई, 1949 को विलय किया गया तथआ संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हुआ।

26 जनवरी, 1950 को संयुक्त वृहद राजस्थान में आबू और देलवाड़ा को छोड़कर रियासत सिरोही का विलय हुआ तथा 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत तत्कालीन अजमेर मेरवाड़ा राज्य का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया जो अब तक केन्द्र शासित 'सी' श्रेणी का राज्य था। इसी के साथ मध्य भारत का सुनेल टप्पा क्षेत्र का राजस्थान में विलय हुआ। झालावाड़ जिले का उप जिला सिरोंज को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया।

राजस्थान निर्माण के अंतिम चरण में ही विधान परिषद् की स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ हो गई थी। यह प्रक्रिया वर्ष 1952 के आरम्भ तक चलती रही। इसी दौरान श्री हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 26 अप्रैल, 1951 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। राजस्थान विधान सभा मार्च, 1952 में अस्तित्व में आयी। अजमेर विधान सभा के विलय के पश्चात पहली विधान सभा में 160 सदस्य थे। दूसरी एवं तीसरी विधान सभा में 176 सदस्य, चौथी एवं पांचवीं में 184 सदस्य तथा छठी विधान सभा से अब तक सदस्यों की संख्या 200 है। यह उल्लेखनीय है प्रारम्भिक विधान सभाओं में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हुआ करते थे अर्थात् एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक सामान्य तथा एक सुरक्षित कुल दो विधायक निर्वाचित होते थे।

पहली विधान सभा की बैठक सवाई मानसिंह टाउन हॉल में 29 फरवरी, 1952 को प्रातः 8.30 बजे प्रारम्भ हुई जिसके पहले दिन सदस्यों को शपथ दिलायी गई तथा सत्र के दूसरे दिन 31 मार्च को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के उपरांत राजप्रमुख का उद्घाटन भाषण हुआ। रोचक तथ्य यह है कि आजकल सामान्यतया प्रातः 11.00 बजे से आरम्भ होने वाली सदन की कार्यवाही पहली विधानसभा के दौरान प्रातः 8.00 बजे से आरम्भ होती थी जिसका समय बाद में दूसरी विधान सभा से 11.00 बजे हो गया। हालांकि अपवाद स्वरूप विभिन्न अवसरों पर विधान सभा की कार्यवाही प्रातः 11.00 बजे के इतर भी शुरू होती रही है।

मार्च माह का दूसरा महत्त्वपूर्ण अवसर होता है राज्य का बजट। पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा में चतुर्थ सत्र में 20 फरवरी, 2020 को

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य का वर्ष 2020-21 का आय-व्ययक अनुमान विधान सभा में प्रस्तुत किया। बजट एक निश्चित समयावधि के लिए, सामान्यत: एक वर्ष के लिए, आय-व्यय का पूर्वानुमान होता है। यह सरकार द्वारा आने वाले वर्ष के लिए निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तैयार की गई विस्तृत कार्य-योजना होती है। वित्तीय प्रशासन बजट के माध्यम से ही काम करता है। बजट राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

बजट शब्द का निर्माण फ्रेंच (फ्रांस) भाषा के शब्द 'बोजते' से हुआ जिसका सामान्य अर्थ चमड़े का थैला है। यह शब्द सन् 1733 में इंग्लैण्ड की संसद में बोला गया था। उस समय वहाँ वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने अपनी वित्तीय योजना संसद में प्रस्तुत की जिसे ससंद के ही एक सदस्य ने व्यंग्य में कहा कि वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात् चमड़े का थैला खोला है। भारत में आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग के समय में हुई। इस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी, 1860 को सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 1860 से ही भारत में अप्रैल से मार्च का बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष की प्रणाली शुरू हुई।

भारत सहित अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में मुख्यत: मद-क्रम बजट अर्थात् ऐसा परम्परागत बजट जो विभिन्न मदों पर केवल वित्तीय प्रावधान करता है; को बनाने एवं क्रियान्वयन करने की परम्परा रही है किन्तु विगत सदी के मध्य से बजट की नवीन पद्धतियों यथा-निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, कार्यक्रम बजटिंग तथा वर्तमान सदी में जेण्डर बजट, बालक बजट इत्यादि का प्रचलन शुरू हुआ है। इन्हीं में से एक है - आउटकम अर्थात् परिणामोन्मुखी बजट।

भारत में आउटकम बजट अवधारणा वर्ष 2005-06 के आम बजट की प्रस्तुति करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के बजट भाषण से लागू हुई। यह वह अवधारणा है जो परम्परागत बजट प्रावधानों या परिव्यय के बजाय प्राप्त होने वाले भौतिक लक्ष्यों पर बल प्रदान करती है। जिन मंत्रालयों या विभागों के कार्यक्रमों के परिणामों को मात्रात्मक रूप से मापना संभव नहीं होता है, उन्हें इस प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसी को आधार मानते हुए केन्द्रीय स्तर पर घोषणा होने के बाद राजस्थान का प्रथम आउटकम बजट मार्च, 2007 में सामने आया जिसमें वर्ष 2005-06 के बजट प्रावधानों तथा तत्सम्बन्धी अर्जित उपलब्धियों का मूल्यांकन था।

यदि इतिहास के झरोखे में हम झांकें तो पाते हैं कि 7 अप्रेल, 1952 को पहली बार विधान सभा में वर्ष 1952-53 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया। पहले बजट भाषण को सदन में प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा ने राज्य के वित्तीय हालातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 'मेरा सौभाग्य है कि इस सदन के प्रति उत्तरदायी प्रथम मंत्री मण्डल के प्रथम आय-व्ययक प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य मेरे ऊपर आया है। यदि हमारे व्ययक में सामाजिक सेवाओं के लिये पर्याप्त व्यवस्था होती, जिसकी कि परम आवश्यकता है, तो मेरा कार्य और भी सुखकर होता। हमारी सम्पूर्ण कहानी मुसीबतों और कठिनाइयों से भरी है। परन्तु यदि मैं आज की आर्थिक व्यवस्था का चित्र इस सदन के सम्मुख उपस्थित न करूं तो इस सदन के सेवक के रूप में मैं अपने कर्तव्य से च्युत हुआ समझा जाऊंगा...।' इस भाषण में उन्होंने विधान सभा गठन से पूर्व वर्ष 1951-52 के आय-व्ययक में 15.00 लाख रुपये के घाटे का भी उल्लेख किया। राज्य के विधायी कार्यों का साक्षी रहे सवाई मानसिंह टाउन हॉल में ग्यारहवीं विधान सभा के पाँचवें सत्र के आखिरी दिन अर्थात् दिनांक 6

नवम्बर, 2000 तक सदन की बैठकें हुईं। इसी टाउन हॉल में 30 मार्च, 2000 को वित्त मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह ने राज्य का अंतिम बजट भाषण दिया था।

सवाई मानसिंह टाउन हॉल से लालकोठी के नवीन भव्य भवन तक की राजस्थान विधानसभा की यह यात्रा केवल सुविधाओं और आधुनिक भव्य भवन में प्रवेश मात्र न होकर उन परम्पराओं और कार्यशैलियों का भी आधुनिकीकरण है जो रजवाड़ों की सामन्ती परिषदों के शुरू होकर जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में तत्कालीन राज प्रमुख महामहिम महाराजा मानसिंह के उद्घाटन अभिभाषण से हुई थी। नवीन विधान सभा भवन में ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र से बैठकें आरम्भ हुई। 27 मार्च, 2001 को प्रातः 12.42 बजे सदन की बैठक आरम्भ हुई। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री परसराम मदेरणा ने इस दिन नवीन भवन में विधायकों का स्वागत किया। यह भी सुखद था कि नवीन भवन में प्रथम बजट भाषण देने वाले भी श्री प्रद्युम्न सिंह ही थे। श्री सिंह ने 29 मार्च, 2001 को नवीन भवन में पहला बजट भाषण दिया था।

परिवर्तित और संशोधित बजट भाषण को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 78 बजट भाषण विधान सभा में दिये जा चुके हैं। इनमें से 54 भाषण सवाई मानसिंह टाउन हॉल में दिये गये तथा शेष 24 बजट भाषण इस वर्तमान विधान सभा भवन में दिये गये। हास्य और व्यंग्य सदन की कार्यवाही का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। इनके कारण सदन का वातावरण सरस बना रहता है। बजट के दौरान भी हास्य एवं व्यंग्य के दृश्य उपस्थित होते रहे हैं। वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतिपक्षी दल को उनकी नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ' नोटबंदी से बर्बादी पर वो बोलते नहीं, जीएसटी के झटकों पर मुंह खोलते नहीं, उनके आंकड़े ही दिखाते हैं उन्हें आईना, वो फिर भी मुकरकर सच को तौलते नहीं।' उन्होंने आगे अपने भाषण के समापन पर कहा कि 'जिन्दगी की अभी असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं, आगे अभी सारा आसमां बाकी है।' उल्लेखनीय है कि श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के 12 बजट भाषण दिये हैं तथा श्री अशोक गहलोत ने अब तक 9 बजट भाषण सदन में दिये हैं। श्री चन्दनमल बैद ने भी 9 बजट भाषण दिये थे।

राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परम्पराएं रही हैं जो अन्य राज्य विधान मण्डलों के लिए अनुकरणीय है। राजस्थान के विधायक जहां राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए सदैव चिन्तनशील रहे हैं। वहीं विधानसभा की परम्पराओं, परिपाटियों और प्रतिमानों के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही है। निःसंदेह भविष्य में भी पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्य मिलकर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। •

गांधी दर्शन के संकल्प का समावेशी बजट

– डॉ. बी. एल. सैनी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1925 को समाज में व्याप्त सात सामाजिक पापों की एक सूची अपने किसी अंग्रेज मित्र को भेजी थी। फिर उसे 22 अक्टूबर, 1925 के **यंग इंडिया** में भी प्रकाशित किया था। गांधीजी चाहते थे कि पढ़ने वाले इन बातों पर बुद्धि से नहीं, दिल से सोचें और इनसे अपने जीवन में बचने की कोशिश करें। जब गांधीजी ने इन्हें अपने पाठकों के लिए प्रकाशित किया होगा, तब उनकी भी यही इच्छा रही होगी। वे भी इन सात सामाजिक पापों से मुक्त होने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते होंगे। उन सात सामाजिक पापों की सूची इस प्रकार है- 1. सिद्धांत विहीन राजनीति, 2. कर्म विहीन धन, 3. आत्मा विहीन सुख, 4. चरित्र विहीन ज्ञान, 5. नैतिकता विहीन व्यापार, 6. मानवीयता विहीन विज्ञान, 7. त्याग विहीन पूजा।

गांधीजी के अनुसार नैतिकता, अर्थशास्त्र, राजनीति और धर्म अलग-अलग इकाइयां हैं, पर सबका उद्देश्य एक ही है- सर्वोदय। ये सब यदि अहिंसा और सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी अपनाने योग्य हैं। राजनीति यदि लक्ष्यहीन है, निश्चित आदर्शों पर नहीं टिकी, तो वह पवित्र नहीं। राजनीति से मिली शक्ति का उद्देश्य है- जनता को हर क्षेत्र में बेहतर बनाना। तटस्थता, सत्य की खोज, वस्तुवादिता और नि:स्वार्थ भाव एक राजनेता के आदर्श होने चाहिए। स्वेच्छा से सादा जीवन अपनाना और निजी वस्तुओं का त्याग, राजनेता के लिए अनिवार्य कर्म है। धन बिना कर्म के मंजूर नहीं होना चाहिए, अनुचित साधनों से बिना परिश्रम से कमाया गया धन अस्तेय नहीं, चुराया हुआ धन है। अपने लिए जितना जरूरी हो, उतना रखकर बाकी जनता की अमानत समझकर न्यासी भाव से उसे कल्याण कामों में लगाना धनी व्यक्ति का कर्तव्य है। आत्मा के अभाव में सभी प्रकार के सुख सिर्फ भोग और वासना मात्र हैं।

"बजट असल में वर्षभर की योजनाओं के आंकलन के साथ भविष्य की कार्य योजना का संतुलित पत्रक होता है। स्वाभाविक ही है कि इसके अंतर्गत योजनाओं का ताना बाना कुछ इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जिससे समग्र क्षेत्रों में संतुलित विकास को व्यवहार में परिणत किया जा सके। इस दृष्टि से राजस्थान सरकार के बजट में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विद्युत एवं पेयजल, महिला एवं बाल विकास के साथ युवाओं को भविष्य के लिए बेहतरीन तकनीक एवं कौशल युक्त बनाने पर पर्याप्त जोर सात संकल्पों के जरिये रखा गया है। यही इस बजट की वह विशेषता है, जिसके जरिये इसे गांधी दर्शन प्रेरित सर्वोदयी सोच का बजट कहा जा सकता है।"

आत्मा से उनका अभिप्राय उस आंतरिक आवाज से है जो आत्म अनुशासन से सुनाई पड़ती है। यही गलत और सही का विवेक देती है। दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख पाप है, अस्थायी है। यदि इस सुख को स्थायी बनाना है तो पहले मूलभूत सुखों से वंचित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। मनुष्य का लक्ष्य पवित्र होते हुए भी ज्ञान के बिना गलत रास्तों पर चलने का खतरा रहता है। चरित्र पर कलंक लग जाता है। सुंदर चरित्र या व्यक्तित्व के बिना ज्ञानी भी कभी-कभी पापी की कोटि में आ जाता है। राम के भक्त गांधीजी, राम को प्रत्येक नागरिक में देखना चाहते थे। व्यापार में अक्सर नैतिकता कुर्बान हो जाती है, व्यापारी निजी और पेशे की नैतिकता को अलग-अलग तत्व मानते हैं। जरूरत से ज्यादा नफा लेने वाला व्यक्ति यदि अपनी दुकान पर ग्राहक का छूट गया सामान लौटा देता है तो भी वह नीतिवान नहीं माना जाएगा। जमाखोर किसी डाकू से कम नहीं होते। पूजा त्याग के अभाव में कर्मकांड मात्र रह जाती है। जीवन में धर्म का महत्व गांधीजी ने हर क्षेत्र में माना। परंतु धर्म भी आत्मविकास का साधन है। छोटे-छोटे स्वार्थों और आसक्तियों का त्याग विकास को पूर्णता की ओर ले जाता है। दूसरे धर्मो के प्रति आदर और सहनशीलता का भाव अहिंसा और सत्य का पालन है। दूसरे के धर्म में दखल देना, दूसरे धर्मावलंबियों को चिढ़ाने और लड़ने के मौके ढूंढना-पूजा की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

इसी ध्येय को केन्द्र में रखते हुये राजस्थान की जन कल्याण की परम्परा का निर्वाह करते हुये मुख्यमंत्री जी ने राज्य विधायिका के सम्मुख 20 फरवरी,2020 को राज्य का बजट और आगे के वित्तीय वर्ष के बजट के प्रस्ताव रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री राज्य के किसानों-पशुपालकों, महिलाओं, छात्रो-युवाओं, औधोगिक एवं व्यापरिक संगठनो, सिविल सोसायटी आदि से बजट पूर्व चर्चा कर एक समावेशी बजट बनाया है जिसको सरकार के निम्न सात संकल्पों में समझ सकते है-

निरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान,महिला-बाल-वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़को का मान तथा कौशल व तकनीक प्रधान।

इन संकल्पो से यह प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग एवं आम जनता की आवश्यकताओ को पुरा करने की है। बजट में गांधी दर्शन की अप्रत्यक्ष झलक भी दृष्टिगोचर होती है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने राजस्थान के सभी क्षेत्रों से जुड़े जनकल्याण को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध सोच का पैमाना बजट में अपनाया है। महात्मा गांधी का दर्शन समग्र कल्याण के साथ व्यावहारिक सोच से जन सेवाओं के बेहतर संपादन पर केन्द्रित है। इसके लिए राजनीति, अर्थशास्त्र, नैतिकता के अतर्गत सर्वोदय की बात गांधीजी ने कही है। राजनीति के अंतर्गत आमजन को प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास होने चाहिए, यही गांधी का मूल दर्शन रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में श्री गहलोत का बजट पूरी तरह से खरा उतरता प्रतीत होता है।

बजट असल में वर्षभर की योजनाओं के आंकलन के साथ भविष्य की कार्य योजना का संतुलित पत्रक होता है। स्वाभाविक ही है कि इसके अंतर्गत योजनाओं का ताना बाना कुछ इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जिससे समग्र क्षेत्रों में संतुलित विकास को व्यवहार में परिणत किया जा सके। इस दृष्टि से राजस्थान सरकार के बजट में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विद्युत एवं पेयजल, महिला एवं बाल विकास के साथ युवाओं को भविष्य के लिए बेहतरीन तकनीक एवं कौशल युक्त बनाने पर पर्याप्त जोर सात संकल्पों के जरिये रखा गया है। यही इस बजट की वह विशेषता है, जिसके जरिये इसे गांधी दर्शन प्रेरित सर्वोदयी सोच का बजट कहा जा सकता है।

सात संकल्पों का सर्वकल्याणकारी बजट

– डॉ. सत्यनारायण सिंह

इस बार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है, वह इस मायने में लीक से हटकर है कि उसके सात संकल्पों के जरिए सर्वकल्याण की सोच को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। बजट राज की वार्षिक योजना का एक तरह से लेखा-जोखा होता है, स्वाभाविक ही है-इसके जरिए सरकारें आमजन के लिए चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अशोक गहलोत जी ने इस बजट में वही किया है। उन्होंने संकल्पों के जरिए जन कल्याण के लिए संवेदनशील होकर विचार किया है।

बजट में जन घोषणा-पत्र में लिए गये सात संकल्पों की दिशा में किसानों के लिए 1000 करोड रूपये का कृषि कल्याण कोष, सहकारी ऋण माफी, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता क्लिनिक, महिलाओं के उत्थान के लिए 1000 करोड़ इन्दिरा महिला शक्ति निधि, 1 लाख युवाओं को 1000 करोड़ के ऋण के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, राजस्थान जन आधार योजना, खेलों को प्रोत्साहन हेतु राज्य खेलों के आयोजन की घोषणा की थी।

इस वर्ष बजट में एक नई शुरुआत करते हुए सात संकल्पों के साथ एक नई बजट प्रणाली प्रारम्भ की। सात संकल्पों में पहला निरोगी राजस्थान, दूसरा सम्पन्न किसान, तीसरा महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, चौथा सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान, पांचवां शिक्षा का परिधान, छठा पानी बिजली व सड़को का मान, सातवां कौशल व तकनीक प्रधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्तुत करते समय स्पष्ट उद्देश्य एवं दृष्टिकोण रखा। बजट में यह एक नई परिपाटी है, जो स्वागत योग्य है। सरकार किन-किन क्षेत्रों को महत्त्व देकर, लक्ष्य निर्धारित कर, राज्य को आगे बढ़ाना चाहती है, स्पष्ट अंकित होता है। राजस्थान बजट में कवायद यह है कि युवाओं को रोजगार मिले, फसल के साथ किसानों के चेहरे खिले। नये अधिनियमों को लाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कदम बढ़ाया गया है। किसानों को कृषि उपकरण मुहैया कराने का नवीन प्रस्ताव है। नौकरियों के नवीन अवसर होने से शिक्षित युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है। औद्योगिक विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के लिए वन स्टाप शॉप प्रणाली स्थापित कर प्रक्रिया को सरल करने की कोशिश की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए हाईटेक वाहन, मोबाइल पुलिस, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जिला कलक्टरों को ड्रोन उपलब्ध कराये जायेंगे। खेती, युवा, सुरक्षा पर फोकस रखा गया है। बजट में किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। किसानों को बीज, खाद और लेटेस्ट तकनीक का प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए पहल स्वागत योग्य है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। निरोगी राजस्थान संकल्प से बजट को नई गति मिलेगी साथ ही स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी विभिन्न विभागों पर भी जोर दिया गया है। जिला स्तर पर अरली इंटरिवेशन सेंटर स्थापित करने तथा मिलावटखोरी रोकने के लिए प्राधिकरण बनाने, मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही के जिलास्तर पर अलग से फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना से आम लोगों को राहत मिलेगी और मिलावटखोरी पर अंकुश लगेगा।

जिला अस्पतालों में सीटी स्केन, एमआरआई की सुविधा, अस्पतालों में अतिरिक्त शैय्याओं की व्यवस्था, नये मेडिसिन विभाग की स्थापना, नवीन होम्योपैथी व आयुष अस्पतालों की स्थापना, मेडिकल कालेज में पृथक से पीडियोट्रिक विभाग, पैथ लैब की उचित व्यवस्था से चिकित्सा व्यवस्था का स्तर ऊंचा होगा और मरीजों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को निरोगी बनाने का संकल्प लिया है। बच्चों को शिक्षा और युवाओं को कौशलपरक शिक्षा पर भी फोकस रखा है।

बजट में सामाजिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 7 संकल्पों के साथ वित्तीय प्रावधानों से समयबद्ध क्रियान्विति हो सकेगी। व्यापार सुदृढ करने के उद्देश्य से भी प्रगतिशील कदम उठाये गये है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेश बोर्ड के गठन से निवेश को बढ़ावा देना, एक अच्छा कदम होगा।

बिजली उत्पादन को इकोफ्रेंडली बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। हर घर नल, साफ पेयजल संकल्प के साथ पीने के पानी की सुविधा पर ध्यान दिया गया है। जल वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण व आधुनिकीकरण को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। बिजली के क्षेत्र में सरकार का फोकस ग्रामीण स्तर पर अधिक है। ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक व्यय करने के साथ क्षेत्र में सड़कों की दुरूस्ती पर पूरा ध्यान दिया गया है। प्रथम बार आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है एवं निजी अस्पतालों को दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए जोड़ा गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षा, चिकित्सा, खेती, युवा और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इससे जवान सशक्त होंगे, किसान खुशहाल होगा और रोजगार बढ़ेंगे।

राज्य सरकार को केन्द्रीय करों से कम राशि मिलेगी। राजस्व प्रबंध में बढ़ोतरी संभव नहीं है। जीएसटी लागू होने पर अड़चनों को दूर करने, व्यापारियों को सुविधाएं देने के लिए वाणिज्यकर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जायेगा। जीएसटी ऑडिट व एंटीइवेजन कार्य बेहतर ढंग से हो सकेगा। वित्त विभाग में ऑडिट प्राधिकरण एवं विदेश इंटीलिजेंस यूनिट का गठन होगा। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मार्गों पर रेडियो फ्रिकवेंसी आईडेंटीफिकेशन केमरे लगाये जायेंगे, आर्थिक अपराध रोकने के लिए कदम उठाये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा पट्टों पर डीएलसी के स्थान पर पट्टों पर वसूल की गई राशि पर स्टांप डयूटी लगाई जायेगी। बकाया भुगतान करने पर ब्याज और शास्ती में छूट दी जायेगी, रियल एस्टेट को मंदी से उभारने के लिए घटाई गई डीएलसी दर तर्कसंगत होगी एवं आम लोगों को राहत मिलेगी।

बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट रोजगार को बढ़ावा देगा। विभिन्न पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियां, व्यवसाय हेतु ऋण, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार से आम लोगों की चिंताएं जरूर कम होंगी। बजट में छात्र-छात्राओं के बौद्धिक विकास का ध्यान रखा गया है। सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बेग-डे रखने से छात्रों के सर्वांगीण विकास का अवसर मिलेगा, अविभावक व आम लोगों का स्कूलों से जुड़ाव होगा। पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं।

यह बजट सर्वकल्याणकारी है, जन कल्याणकारी योजनाओं पर बल दिया गया है। •

बुल्गा, बोऊगेट, बोगेट शब्दों के सफर से बना

बजट

– महेन्द्र गगन

सरकारों की आमदनी का अधिकांश हिस्सा आमजन के अदा किये गये टैक्स से आता है। किसी भी सरकार के खजाने में यदि एक रुपया आता है तो उसमें 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से आता है। अत: सरकारी खजाने का 68 प्रतिशत पैसा आमजन द्वारा चुकाये टैक्स का होता है। जिसे उसे बुनियादी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं पर खर्च करना चाहिए। सरकार जिस राजनीतिक

सफरनामा

बजट यानी सरकार के आय-व्यय का वह प्रपत्र जिसमें विगत वर्ष के आय-व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत होता है। हमारे यहां बजट आगामी वितीय वर्ष हेतु आवश्यक सरकारी खर्च की सुनिश्चितता प्राप्त करने का प्रावधान है। कह सकते हैं, वित्तीय प्रशासन में बजट ही वह धुरी है जिसमें सरकार की आय व्यय और ऋण आदि से सम्बंधित समस्त क्रियाओं का निर्धारण होता है। अगर बजट में आय-व्यय से अधिक हो तो बचत का बजट कहा जाता है और अगर आय-व्यय से कम हो तो घाटे का बजट कहा जाता है। असल में बजट विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

बहरहाल, बजट शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ है चमड़े का थैला। इसी से बाद में फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट बना। इसके बाद अस्तित्व में आया अंग्रेजी शब्द बोगेट या बोजेट, फिर यही शब्द बजट बना। जिसे अब प्रयोग किया जा रहा है।

भारत में बजट

भारत में बजट की शुरुआत सात अप्रैल, 1860 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1860 में पहला बजट पेश किया। जिसे जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उन्हें भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है। भारत

पार्टी की होती है वह अपना राजनीतिक एजेण्डा भी प्रस्तुत किये गये बजट से हासिल करना चाहती है। उसका उद्देश्य अपने वोट बैंक को खुश करना भी इसके पीछे एक मंशा होती है। अंग्रेजों ने इनकम टैक्स वसूलने की शुरुआत की। वही परंपरा आज देश के स्वतंत्र होने के बाद भी परोक्ष रूप से जारी है। हम इसमें कोई खास परिवर्तन ऐसा नहीं कर पाये हैं जो आमजन के हित में सीधे-सीधे हो। हर बजट में जन हित के दावे तो बड़े-बड़े किये जाते हैं, मगर उसका लाभ उन तक पहुंचने का प्रतिशत बहुत कम है। यह जिस दिन बढ़ेगा सही मायनों में वह बजट जनहित का बजट होगा।

बजट का प्रारम्भ एवं विस्तार

बजट शब्द की पैदाईश फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट की उत्पत्ति हुई। फिर अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, इससे ही बजट शब्द बना है।

'बजट' भारत में 150 साल से अधिक पुराना है। इन वर्षों में बजट पेश किये जाने के समय को लेकर तथा इसे पेश करने के तरीकों को लेकर समय-समय पर बदलाव हुआ है तथा कई नयी परंपराएं अस्तित्व में आयीं, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 शाम 5 बजे पेश किया गया। इसे पेश करने वाले थे- स्कॉटिश बिजनेस मैन सर जेम्स विल्सन।

भारत में लंबे समय तक ब्रिटिश हुकुमत रही है लेकिन उसने भारत में आर्थिक सुधार करने या बजट पेश करने की जरूरत महसूस नहीं की। मगर जब 1857 में पहली बगावत हुई तब मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में कूदे। भारत के कई हिस्सों में विद्रोह के सुर उठने लगे। उस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकुमत का खजाना खाली होने लगा। उस वक्त ब्रिटिश सरकार को बजट की जरूरत महसूस हुई। तब उसने 28 नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत बुलाया। 1860 में पहला बजट आया जिसमें इनकम टैक्स एक्ट था। इस एक्ट ने हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्था को उलट-पलटकर रख दिया। टैक्स पहले भी अंग्रेज सरकार लेती थी, मगर वो किसी खास आधार पर नहीं था। उसमें एक निश्चित आयकर सिस्टम बनाया गया था। जेम्स विल्सन ने ही भारत को उसका पहला बजट दिया। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार व्यापार करने के साधन दे रही है जिससे सफल व्यापार करने की सुगम राह मिल रही है अत: भारतवासियों से उसे टैक्स वसूल करने का अधिकार है। विल्सन अच्छे अर्थशास्त्री थे और थोड़े उदार भी थे। मगर वे यह नहीं देख पाये कि ब्रिटिश सरकार भारतीय व्यापारियों का कितना दमन कर रही है। बावजूद इसके ब्रिटिश हुक्मरानों का दावा रहा कि वह व्यापारियों को सुरक्षित व्यापार करने का मौका दे रही है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सरकार वर्ष 1857 के बाद होने वाले विद्रोह को दबाने में जो खर्च हुआ, उसकी भरपाई करने की मंशा से टैक्स लगा रही थी।

इस प्रकार भारत में पहले इनकम टैक्स एक्ट की नींव 1860 में अंग्रेज सरकार ने रखी। बाद में समय-समय पर बदलाव होते रहे जो सरकारों की मंशा और जरूरत के हिसाब से होते थे। मगर विल्सन ने भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा आर्थिक हथियार बजट के माध्यम से दे दिया जिससे सरकार आसानी से कर के माध्यम से भारतीयों

में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ था। साल 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्तमंत्री आरके षणमुखम शेट्टी (चेट्टी) ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था।

सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री

मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार देश का बजट पेश किया। दूसरे नंबर पर पी. चिदंबरम हैं, जिन्हें 8 बार यह अवसर मिला। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, वाईबी चव्हाण और सीडी देशमुख ने 7-7 बार संसद में देश का बजट पेश किया।

बजट की गोपनीयता

बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बजट प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के दफ्तर 'नॉर्थ ब्लॉक' में ही रहना होता है। बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने परिजनों तक से बातचीत करने अथवा मिलने की अनुमति नहीं होती है। इतना ही नहीं बजट दस्तावेजों को छापने का काम भी नॉर्थ ब्लॉक में बने छापेखाने में ही किया जाता है।

प्रधानमंत्री ने पेश किया था बजट

1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया, उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया।

समय में बदलाव

साल 2000 तक केंद्रीय बजट की घोषणा शाम 5 बजे की जाती थी। यह अंग्रेजों के समय से चली आ रही परंपरा थी। इंग्लैंड के समय के अनुसार बजट पेश किया जाता था, जो कि भारत में शाम 5 बजे होता था। इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म किया। यशवंत सिन्हा ने 2001 में 11 बजे दिन में बजट की घोषणा कर नई परंपरा शुरू की।

रेल बजट का विलय

पहले रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किया जाता था। मोदी सरकार ने 2017 में इस परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। इससे पहले 92 सालों तक दोनों बजट अलग-अलग पेश किए गए।

– साभार

से धन वसूल करने लगी। हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखने का समय भी मान सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के इस एक्ट से बड़े व्यापारी, जमींदार और मध्यववर्गीय व्यापारी सभी परेशान हो गये। क्योंकि सभी करों की दोहरी मार के शिकार हो रहे थे। अंग्रेज सरकार कर द्वारा कमाई गई आमदनी का एक हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने के लिए लगा देती थी और उसी सामान से की कमाई पर फिर से टैक्स वसूल कर लेती थी।

स्वतंत्र भारत का पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर. के . षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया। यह बजट साढ़े तीन महीनों (15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948) के लिए था। 1924 से 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिनों में शाम पांच बजे पेश होता रहा। यह प्रथा बेसिल ब्लैकेट ने प्रारंभ की थी। सन् 2000 में पहली बार इस प्रथा को तोड़कर यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया। बजट में पहली बार अंतरिम बजट को आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 1948-49 पेश किया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जान मथाई ने पेश किया। इसी बजट में योजना आयोग की स्थापना का जिक्र भी किया गया था। वर्ष 1951-52 का अंतरिम बजट सी.डी. देशमुख ने पेश किया। वे रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गर्वनर भी थे।

1955-56 से हिंदी में पेपर तैयार करने की शुरुआत हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का बजट पेश किया था। क्योंकि वे ही देश के वित्त मंत्री थे। वे बजट प्रस्तुत करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी वित्त मंत्रालय अपने पास होने की वजह से बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। उन्होंने छह बार वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया तथा चार बार देश के उप प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। उनके नाम अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी पहली वित्त मंत्री थीं। आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने इस वर्ष का बजट पेश किया।

बजट की गोपनीयता बनाये रखने के लिए बजट बनवाने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के दफ्तर में ही रुकना होता है। यह कार्यालय नई दिल्ली के नार्थ ब्लॉक में स्थित है। वहां रहते हुए किसी को भी अपने परिजनों तक से मिलने नहीं दिया जाता। बजट छपने के लिए भेजे जाने के बाद हलुआ खाने की रस्म निभाई जाती है।

भारत के पहले बजट का खर्च 197.39 करोड़ रुपये था। इसमें से करीब आधा (46 प्रतिशत) हिस्सा डिफेंस सेक्टर को दिया गया था। यह रकम 92.74 करोड़ रुपये थी। उस वक्त देश की सीमाओं की सुरक्षा एक बड़ा लक्ष्य था। पहले बजट में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि भारत और पाकिस्तान सितंबर-1948 तक एक ही करेंसी का इस्तेमाल करेंगे।

संसद में बजट 2019 को पेश करने के दौरान केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्षों पुरानी ब्रीफके स में बजट के दस्तावेजों के ले जाने की पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया। वे ब्रीफकेस के बजाये सभी दस्तावेजों को लाल रंग के कपड़ों में बाँध कर लायी थीं, कपड़े पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न लगा हुआ था। पुराने समय से भारतीय परंपरा में वित्तीय बही-खाता को लाल कपड़े में बाँध कर रखने का चलन रहा हैं। साल 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी वर्किंग डे में पेश किया जाता था।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2017 में इस परंपरा को बदला गया और 1 फरवरी को बजट पेश किया। बजट पेपर पहले सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे, लेकिन बाद में 1955-56 से इन्हें हिंदी में भी छापा जाने लगा। कालाधन

> बजट शब्द की पैदाईश फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट की उत्पत्ति हुई। फिर अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, इससे ही बजट शब्द बना है।
>
> 'बजट' भारत में 150 साल से अधिक पुराना है। इन वर्षों में बजट पेश किये जाने के समय को लेकर तथा इसे पेश करने के तरीकों को लेकर समय-समय पर बदलाव हुआ है तथा कई नयी परंपराएँ अस्तित्व में आयीं, कई कीर्तिमान स्थापित हुए।

घोषित करने को लेकर पहली बार 1965-66 में योजना लाई गई थी। तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 1982 में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था। उन्होंने बजट पेश करने में 95 मिनट का वक्त लिया था जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहना पड़ा- सबसे छोटे वित्त मंत्री ने सबसे लंबा बजट पेश किया।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साल 1987-88 में वीपी सिंह के सरकार छोड़ने के बाद बजट पेश किया। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत की थी। पहली बार एक साल में दो पार्टियों के नेताओं ने अलग-अलग बजट पेश किया। साल 1991-92 का अंतरिम बजट बीजेपी के यशवंत सिन्हा ने पेश किया, जबकि फाइनल बजट मनमोहन सिंह ने पेश किया। यशवंत सिन्हा की ओर से पेश किए गए बजट में सबसे ज्यादा रोल बैक थे। 1991 में उनके बजट पर फोरेक्स क्राइसिस की झलक दिखी थी जबकि 1999 के बजट में पोखरण धमाकों का असर दिखा।

रेल बजट

ऑकवर्थ कमेटी के अध्यक्ष विलियम ऑकवर्थ थे जो ब्रिटिश रेलवे के प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। उनका सुझाव ब्रिटिश सरकार ने 1924 में माना और एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। इसके तहत रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाने लगे। आजाद भारत में भी यह परंपरा 93 साल तक जारी रही। रेल बजट अलग से शुरू होने की परंपरा ब्रिटिश शासन से जुड़ी है। साल था 1924 और इसकी सिफारिश की थी ऑकवर्थ कमेटी ने। उस जमाने में भारत में रेलवे की देखरेख और बड़े फैसलों का दायित्व ब्रिटिश रेलवे पर था। तब ऑकवर्थ कमेटी ने 1920 से 1921 तक अध्ययन कर पाया कि भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाना चाहिए। भारत में रेल बजट का पहला लाइव टेलीकास्ट 24 मार्च 1994 को किया गया। भारत में पहली महिला रेलमंत्री ममता बनर्जी थीं जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। 2002 में वे रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेलमंत्री थीं। ममता बनर्जी के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज है। वे पहली रेलमंत्री थीं जिन्होंने एनडीए और यूपीए दोनों सरकारों में रेल बजट पेश किया। लालू प्रसाद यादव रिकॉर्ड छह बार रेल बजट पेश कर चुके हैं। यही नहीं, कभी उनके घोर राजनीतिक विरोधी रहे नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं। भारतीय रेलवे की गिनती विश्व में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले नियोक्ता में होती है। इंडियन रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रेल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चली थी। इसके बाद पूरे भारत में रेलवे पटरियों का जाल बिछाया गया और रफ्तार भी तेज हुई। आज रेलवे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में केन्द्र सरकार ने रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा समाप्त कर दी है।

भारत के कुछ खास बजट जो अपनी विशेषता के अनुसार जाने जाते हैं :

1951– आजाद भारत का पहला खास बजट

इसी बजट में प्लानिंग कमीशन का रोडमैप तैयार हुआ था। इसे पेश करने वाले थे जॉन मथाई।

1968– डेमोक्रेटिक बजट

इस बजट में **'Spouse Allowance'** खत्म कर दिया गया। जिसमें दोनों पति-पत्नी को इनकम टैक्स भरना होता था। साथ ही ये बजट व्यापारियों के लिए नींव साबित हुआ। पेश करने वाले थे मोरारजी देसाई।

1986– लाइसेंस राज खत्म करने वाला बजट

इस बजट में लाइसेंस राज को कम तवज्जो दी गई थी और देश के आर्थिक विकास के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में फेरबदल किए गए थे। पेश करने वाले थे वी.पी. सिंह।

1987– गांधी बजट

इस बजट में बेहद जरूरी काम किया था उन कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने का जिन्हें फायदा तो बहुत होता था, लेकिन वो कानूनी तौर पर वो इससे बचने में कामयाब हो रही थीं। पेश करने वाले थे राजीव गांधी।

1991– ग्लोबल बजट

ये बजट खासतौर पर आयात और निर्यात पॉलिसी पर ध्यान दे रहा था और इम्पोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट पॉलिसी में अंतर बना कर भारत को ग्लोबल बिजनेस का मौका दिया था। पेश करने वाले थे मनमोहन सिंह।

2000– मिलेनियम बजट

इस बजट में भारत को अहम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब बनाने की बात की गई थी। भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए इसमें बहुत कुछ था। पेश करने वाले थे यशवंत सिन्हा। •

युवा उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट

- भवानी शंकर जोशी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतॉनियो गुटेरेश की पहल पर कुछ समय पहले ही युवाओं के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए सभी क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी आवाजों को ज्यादा अहमियत दिए जाने के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया के करीब एक अरब 80 करोड़ युवा 10 से 24 वर्ष की उम्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मानव इतिहास में इतनी बड़ी युवा आबादी पहले कभी नहीं रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि युवाओं को केन्द में रखते हुए राष्ट्र और राज्य अपनी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करें। वैश्वीकरण, नई टेक्नोलॉजी, श्रम बाजारों के बदलते स्वरूप में युवाओं के लिए नीतिया बनाकर उन पर अमल करना सरकारों के लिए कम चुनौती भी नही है। एक सर्वे के अनुसार इस समय युवाओं की कुल आबादी का 20 प्रतिशत हिस्सा रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण अवसरों से वंचित है। इसीलिए हरेक चार में से एक युवा किसी ना किसी तरह से असंतोष में हिंसा, आत्मघाती कदमों से ग्रस्त है। स्वाभाविक ही है कि युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके शिक्षण-प्रशिक्षण और उन्हें तकनीकी कौशल युक्त बनाने की इस समय सर्वाधिक आवश्यकता है।

इस दृष्टि से राजस्थान मे हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह उम्मीदें जगाने वाला है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अपने इस बजट मे युवाओं को केन्द्र में रखते हुए बहुत सी नवीन पहले की है। मसलन बजट में लगभग सभी विभागों के अंतर्गत जो घोषणाएं की गयी हैं, उनमें युवाओ के रोजगार अवसर बढ़ने की बात तो है ही साथ ही पृथक से भी जो सात संकल्प बजट में रखे गये हैं, उनमें एक पूरा कौशल एवं तकनीक प्रधान पर है। यानी इसके अंतर्गत युवाओं को कौशल और तकनीकी दक्षता के लिए विशेष सोच रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर घोषणाएं की हैं।

युवा किसी भी देश और राज्य के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। कहते हैं, जहां युवाओं को बेहतर अवसर मिलते हैं, वहां तेजी से तरक्की होती है। युवा पीढ़ी ही किसी राष्ट्र और राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नींव तैयार करती है। ऐसे में यह जरूरी है कि युवाओं के लिए सरकारें विशेष सोच रखते हुए कार्य करें। ऐसा लगता है, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इसी सोच के तहत इस बार छात्र, युवा और जवान के लिए बजट के चौथे संकल्प में विशेष ध्यान रखते हुए मंशा जाहिर की है। सातवें संकल्प में तकनीकी और कौशल दक्षता की बात कही गयी है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सात संकल्पों में दो संकल्प पूरी तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केन्द्रित ही है।

इस बजट की खास बात है, राज्य के ऊर्जावान युवाओं के लिए खास प्रावधान रखे गये हैं। 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' खेलों को बढ़ावा

देने के साथ युवाओ को खेल क्षेत्रों में अधिकाधिक अवसर देने की मंशा है परन्तु इसे इस रूप में और समझें कि इसके तहत ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे लाने की बात कही गयी है। यही नहीं ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा बजट में की गई है। यह राशि पहले 75 लाख रुपए थी। इसी तरह रजत जीतने पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब तक यह इनामी राशि 50 लाख थी। वहीं, कांस्य जीतने पर 30 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई। अब तक यह 30 लाख रुपए थी। वहीं, रजत पदक जीतने पर 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने 10 लाख रुपए को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। इससे आने वाले समय में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा बल्कि प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर भी मिलेंगे। बजट में वर्ष 2022 में होने वाले खेल राज्य में 75 करोड़ के स्टार्टअप फंड की घोषणा गई है। इस फंड से युवाओं को स्टार्टअप स्टेबलिस्ट करवाने में मदद की जाएगी। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए 6 हजार युवाओं को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि बजट में सरकार के विभिन्न विभागों में 53 हजार 181 पदों पर भर्ती निकाले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की है इनमें मेडिकल एंड हेल्थ विभाग में 4369 पदों पर, मेडिकल एजुकेशन में 573 पदों पर, कॉ-ऑपरेटिव में 1000 पदों पर, एजुकेशन में 41 हजार पदों पर, लॉकल-सेल्फ गर्वनमेंट में 1039 पदों पर, गृह विभाग में 5000 पदों और जीएडी में 200 पदों पर भर्तियां निकाले जाने की बात कही गयी है। बजट के बाद एक समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश मे रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां किए जाने के लिए निर्देश भी जारी किए। यानी सरकारी क्षेत्र मे युवाओं को अवसर देने के साथ ही कौशल विकास के लिए कौशल वृद्धि और रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की बात भी विशेष रूप से कही गयी है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने की घोषणा इसी की महत्ती कड़ी है। प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कंटेंट बैंक की स्थापना करते हुए कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिए गए लेक्चर को रिकॉर्ड करने आदि से विद्यार्थियों को शिक्षण के स्तर में तेजी से सुधार आएगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

यह भी कम महत्त्वपूर्ण नही है कि इस बजट में राज्य में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर का बनाने की घोषणा की गयी है। बाकायदा इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी 229 राजकीय आईटीआई में युवाओं को ई-क्लास रूम के माध्यम से प्रशिक्षण देने, राजीव गांधी स्किल प्रोग्राम के तहत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय (आरआईएसयू) के सहयोग से उभरती हुई तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स एवं रोबोटिक ऑन लाइन डिजिटल कौशल के कोर्सेज शुरू किए जाने की बजट की बातें भी ऐसी ही है जिनके अंतर्गत युवाओ के कौशल और तकनीकी दक्षता से उन्हें आगे बढ़ाने की मंशा श्री गहलोत ने जाहिर की है।

श्री अशोक गहलोत सुलझी सोच के परिपक्व मुख्यमंत्री है। उनके पास अपना काम करने का नजरिया और स्वयं की राजनीतिक सोच है। दीर्घकालीन विकास के लिए युवाओं के लिए कार्य करने की उनकी मंशा आरंभ से रही है। इस बजट में उन्होंने युवाओं के लिए जिस तरह से अपनी घोषणाएं की हैं, वह प्रदेश के दूरगामी विकास को ध्यान मे रखने के साथ ही युवाओ की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल कर इस शक्ति का राज्य के हित में उपयोग करने की उनकी सुमंशा ही दर्शाता है। बजट इस मायने में लीक से हटकर भी है कि इसमें युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने के साथ ही यह उनकी क्षमता वर्द्धन पर केन्द्रित हैं। यानी युवाओं को सभी स्तरों पर सक्षम बनाना चाहे वह खेल हो, रोजगार हो या फिर शिक्षा के उनके स्तर में वृद्धि करते उनके सर्वांगीण विकास की बात हो-यह बजट भविष्य की सुनहरी उम्मीदें लिए है।•

बजट : पर्यटन एवं आयुर्वेद

– डॉ. विजय प्रकाश गौतम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नवीन पी.जी. छात्रावास एवं वर्तमान स्नातक छात्रावास के निर्माण एवं विस्तार की घोषणा की है। आयुर्वेद विकास की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से इस समय आयुर्वेद को जोड़कर चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान दिया जाये तो आर्थिक दृष्टि से बहुत कुछ महत्वपूर्ण हासिल हो सकता है। बजट में 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष के अन्तर्गत चिकित्सा पर्यटन को भी नये आयाम मिलेंगे।

राजस्थान में चिकित्सा पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। जरूरत इस बात की भी है कि सुनियोजित सोच के साथ चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाये।

विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार – पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करने अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह दौरा ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष के लिए मनोरंजन, व्यापार व अन्य उद्देश्य से किया जाता है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मानव के विकास, सुख, शान्ति, संतुष्टि व ज्ञानवर्द्धन के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना है। वर्तमान में पर्यटन एक वैश्विक वृहत उद्योग बन गया है जिसके माध्यम से आर्थिक समृद्धि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, समग्र मानविकी विकास व विदेशी मुद्रा भंडार का अर्जन किया जा सकता है।

आजकल पर्यटन के क्षेत्र में वैलनेस ट्यूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन का महत्व भी वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। भारत का केरल राज्य आयुर्वेद पर्यटन की दृष्टि से आदर्श एवं प्रेरक राज्य है। स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से आयुर्वेद में पर्यटकों को आकर्षित करने की विपुल संभावना है। आज की भागदौड़ की जीवन शैली, तनावपूर्ण वातावरण कार्यालयों के अधिक काम काज की वजह से निरन्तर तनाव बढ़ता जा रहा है जिससे जीवन शैली जन्य व्याधियों यथा मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, अवसाद, अनिद्रा, ज्वाइंट पेन, रोग प्रतिरोधक क्षमता की न्यूनता, उच्च रक्तचाप, कैन्सर, एलर्जी, श्वांस, त्वचा की बीमारी आदि में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

आयुर्वेद विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो मनुष्य के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में अपना सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। आयुर्वेद शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य व सामाजिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करता है। आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। आयुर्वेद उपचार पूर्ण रुप से प्रकृति के समीप है व केमिकल्स व टोक्सिन से मुक्त है। इससे किसी

भी प्रकार की हानि नहीं होती। यही कारण है कि आज विकसित राष्ट्र आयुर्वेद की निरापद चिकित्सा की और आकर्षित हो रहे हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयुर्वेद पर्यटन के तहत इन विधाओं का उपयोग किया जा सकता है–

- व्यक्ति की प्रकृति निर्धारण
- आदर्श जीवन शैली की जानकारी
- विभिन्न प्रकार के मसाज
- मुख स्वास्थ्य के लिए अवल– गंडूप
- नेत्र स्वास्थ्य के लिए नेत्र परिषेक, नेत्र तर्पण
- शरीर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, योग, आसन
- दीर्घायु एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक हेतु उपचार
- मोटापा कम करने के लिए उदवर्तन – स्वेदन उपचार
- सौंदर्य संवर्धन हेतु विभिन्न उपचार
- विभिन्न दर्दनाशक उपचार
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन हेतु रसायन चिकित्सा
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन हेतु पंचकर्म उपचार
- शारीरिक एवं मानसिक शांति हेतु योग एवं आध्यात्मिक उपचार
- आहार विधि विधान
- आर्युवेदीय पाक कला

व्यक्ति की प्रकृति कैसी है इसे ध्यान में रखकर रोग, आहार औषध का निर्धारण किया जाता है साथ ही साथ उसे स्वस्थ रहने के लिए मार्गदर्शित किया जाता है। आदर्श जीवन शैली की जानकारी दी जाती है। इसके अभाव में संपूर्ण विश्व रोगाक्रान्त होता जा रहा है। हमारी दिन चर्या, रात्रिचर्या किस प्रकार की है। इसको ध्यान में रखने के साथ ही ऋतु अनुसार आहार विहार की जानकारी देकर आदर्श जीवन शैली की और प्रेरित किया जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के औषधीय तेलों से शरीर की आकृति व मर्मों के अनुरूप अम्यंग यानी मसाज किया जाता है। जिससे त्वचा सौंदर्य, शारीरिक ऊर्जा व रक्त संचरण सामान्य, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना, मलों का निष्कमार्ग, शरीर में लघुता, ऊर्जा, सक्रियता की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि, बलवर्धक, एकाग्रता में वृद्धि, आत्म बलवृद्धि, युवावस्था में वृद्धि होती है और अनिद्रा दूर होती है।

मुख स्वास्थ्य के लिए कवल - गंडूप - औषध युक्त वक्षाप, तेल, दूध, हिम व अन्य औषधियों के कुछ समय तक मुंह में धारण रखना जिससे दांतों कें मजबूती, मुंह से दुर्गन्धनाश, स्वाद का सम्यक बना रहना व मुंह में तरो-ताजगी बनी रहती है। नेत्र स्वास्थ्य के लिए नेत्र परिवेष, अस्च्योतन-तर्पण - नेत्र खुजली आदि समस्याओं को दूर करने के लिए श्वांस एवं हिम के द्वारा नेत्र प्रक्षालन आंखों में दवा डालना या कुछ समय तक दवा डाल के रखना आदि के द्वारा नेत्र स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। शरीर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम योग आदि किया जाता है। सम्पूर्ण विश्व में शरीर को स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल बनाने के लिए योग ग्रहण कर लिया गया है। व्यायाम से जहां शरीर में दृढ़ता सोष्ठव प्राप्त होती हैं व योग द्वारा अनेक बीमारियों दूर की जा सकती है।

दीर्घायु एवं रोग प्रति रोधक क्षमता वर्धन हेतु शिरोधारा, सर्वांग धारा आदि अनेक उपचार है जिसके माध्यम से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। वहीं आयुष्य में वृद्धि होती है। शरीर पर विभिन्न चूर्णों द्वारा मसाज(वुदवर्तन) खेदक क्रिया, वमन क्रिया एवं विरेचन क्रियाओं के माध्यम से मोटापा दूर किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के लेप उपभोग त्वचा रोग रोग नाशक उपचार टबवाश इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से सौंदर्य संवर्धन किया जा सकता है। जानुबस्ति के माध्यम से घुटनों का दर्द, कटिबस्ति से कमर का दर्द दूर किया जा सकता है।

ये सब आयुर्वेदिक क्रियाएं काफी लोकप्रिय हैं एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। बीमारियां एवं वृद्धावस्था को दूर करने वाली औषधियां एवं तकनीक को रसायन कहते है। विभिन्न रसायन औषधियों का निर्माण कर विपणन व साथ ही मनोहारी, रमणीय वातावरण उपलब्ध कराकर शारीरिक एवं मानसिक तनाव दूर कर अतिरिक्त ऊर्जा व संतुष्टि आयुर्वेद पर्यटन का मूल हो सकता है।

आयुर्वेद पर्यटन के अन्तर्गत इधर विभिन्न रोगों के स्थायी उपचार हेतु पंचकर्म चिकित्सा बेहद लोकप्रिय हो रही है। केरल पूरे विश्व में इस चिकित्सा में विशेष स्थान रखता है। यह चिकित्सा पर्यटकों को विशेष रुप से आकर्षित करती है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य संवर्धन एवं मानसिक शांति के लिए योग-यम-नियम-आसन मेडिटेशन आदि भी आयुर्वेद पर्यटन का मूल आधार है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ के लिए किस प्रकार का आहार लेना - आहार का समय मात्रा प्रकृति अनुसार आधार आदि की जानकारी व पर्यटन एप्स पर आधार की उपलब्धता। आयुर्वेद पर्यटन एप्स पर एक रेस्टोरेंट चलाया जा सकता है जहां पर विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदीय सूप-भूप-रागी-माक-अखरोट, लड्डू आदि की उपलब्धता हो सके।

आयुर्वेद में पर्यटन की विपुल संभावना है परन्तु इसके लिए आवश्यकता है कि-

- मनोहारी - रमणीय स्थल का चयन हो
- पंचकर्म विख्यात चिकित्सक की उपलब्धता
- समर्पित एवं योग्य स्टाफ की नियुक्ति
- औषधियां गुणवत्ता पूर्ण हो
- विश्व स्तरीय साज-सज्जा युक्त भवन
- रेस्टोरंट - भोजनालय पूर्ण हाइजनिक

इन सुविधाओं से सुसज्जित व्यवस्थाओं साथ ही प्रदेश में आयुर्वेद पर्यटन को नये आयाम दिये जा सकते हैं। पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य घटक है। राजस्थान में आयुर्वेद पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। पिछले कुछ समय के दौरान उदयपुर, शेखावटी क्षेत्र, जोधपुर, अलवर आदि में आयुर्वेद पर्यटन से जुड़े विशेष स्थलों का विकास भी हुआ है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज होटल योजना के अन्तर्गत भी आयुर्वेद चिकित्सा से पर्यटकों को विरासत महत्व के स्थलों पर आकर्षित किये जाने के निरन्तर प्रयास हो रहे है।

कोरोना वायरस ने इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। इस वैश्विक आपदा के समय में भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर ही विशेष जोर दिया जा रहा है। यह सुखद है कि जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि अर्जित की गई है। ऐसे समय में विशिष्ट चिकित्सा दल द्वारा किए गए प्रयासों से राजस्थान की देशभर में विशिष्ट पहचान बनी है। चिकित्सा पर्यटन की दृष्टि से यह बड़ी उपलब्धि है।

भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान में किले, महलों, दूर तक पसरे रेगिस्तान, सुरम्य झीलों के पर्यटन स्थलों के साथ ही इधर पर्यटन के नये रूप पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, उनमें आयुर्वेद पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बहुत कम खर्च पर यहां पर बेहतरीन आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाओं की प्राकृतिक स्थलों पर उपलब्धता है। इस दृष्टि से आयुर्वेद पर्यटन के विकास की राजस्थान में विशेष संभावनाएं हैं।•

जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है
अपने इरादों का इम्तिहां अभी बाकी है,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं,
आगे अभी सारा आसमां बाकी है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी 2020 को राजस्थान विधान सभा में वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास का अपना मंतव्य प्रकट किया।

श्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा, 'हमारे लिए सम्पूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है और इस परिवार के लिए मैं, सात संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकताएं बनाना चाहता हूँ

पहला संकल्प - **निरोगी राजस्थान**
दूसरा संकल्प - **संपन्न किसान**
तीसरा संकल्प - **महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण**
चौथा संकल्प - **सक्षम मजदूर, छात्रा-युवा-जवान**
पांचवां संकल्प - **शिक्षा का परिधान**
छठा संकल्प - **पानी, बिजली व सड़कों का मान**
सातवां संकल्प - **कौशल व तकनीक प्रधान**

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि 'मैं वर्तमान की चुनौतियां समझता हूँ और आप सभी के सहयोग से इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहता हूं।'

बजट 2020-21

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया। बजट का अविकल रूप यहां पाठकों के लिए दिया जा रहा है। - संपादक

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- बजट, वर्तमान और आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण तो पेश करता ही है, साथ ही यह सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है। हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकताएं क्या हों, इसके लिए हमने कृषकों-पशुपालकों, महिलाओं, छात्राओं-युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसायटी आदि के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है।
- प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आने वाले वर्ष में हम कौन-कौन से दूरगामी कदम उठाना चाहते हैं, इसका ब्यौरा देने से पहले यह समीचीन है कि मैं, देश की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करूं। इसका जिक्र करने का कारण यह भी है कि, हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर करती है। आज देश की अर्थव्यवस्था के अधिकतर

सूचकांक यह संकेत दे रहे हैं कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है।

- विश्व बैंक, IMF एवं ADB ने विकास दर के अनुमानों को Downgrade किया है। स्वयं केन्द्र सरकार के आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार देश की जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत अनुमानित है। देश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017-18 में पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत दर्ज की गयी है। लम्बे समय बाद उपभोक्ता मांग घटी है। आईआईपी (Index of Industrial Production) manufacturing एवं construction sector के आंकड़े भी निराशाजनक हैं। महंगाई की दर दिसंबर, 2019 में 7.35 प्रतिशत दर्ज हुई है। यहां तक कि कृषि की भी विकास दर थम-सी गई है। उपर्युक्त सभी आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है।

''नोटबंदी से बर्बादी पर वो बोलते नहीं

जीएसटी के झटकों पर मुँह खोलते नहीं,

उनके आँकड़े ही दिखाते हैं उन्हें आईना

वो फिर भी मुकर कर सच को तौलते नहीं।''

- केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में जो गिरावट आ रही है, उसके खामियाजे के रूप में हमारे प्रदेश को share in central taxes मिलता है उसमें 10 हजार 362 करोड़ रुपये काटे जा रहे हैं। केन्द्र सरकार तो कई तरीकों से धन जुटा लेती है, जैसे RBI से रुपये लेकर, Air India-BPCL में विनिवेश करके, LIC में हिस्सेदारी कम करके। जबकि राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है।

- लेकिन, मैं इन चुनौतियों के बावजूद भी माननीय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता का यह कथन **'मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं'** मुझे हर पल प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हमें एहसास है कि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है। इसलिए, इस बजट में हमने कोशिश की है कि विकास की राह बाधित ना हो।

- पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हमें विरासत में लगभग 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज तो मिला ही है, इसके साथ ही, लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के स्वीकृत किये गये कार्यों के भुगतान का भार भी हमारी वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसके चलते कुछ विभागों के संवेदकों http://finance.rajasthan.gov.in/ (3) के बकाया बिलों के भुगतान समय पर नहीं हो पाये।

- गत बजट में हमने **जन-घोषणा पत्र** में लिए गये संकल्पों की दिशा

राष्ट्रपिता का यह कथन 'मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं' मुझे हर पल प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हमें एहसास है कि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है। इसलिए, इस बजट में हमने कोशिश की है, कि विकास की राह बाधित ना हो।

में कई बड़े कदम उठाये थे-किसानों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का **कृषक कल्याण कोष**, सहकारी ऋण माफी, घर के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए **जनता क्लिनिक**, महिलाओं के उत्थान के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की **इंदिरा महिला शक्ति निधि**, एक लाख युवाओं को कुल 1 हजार करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए **मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना**, प्रदेश के निवासियों के लिए **राजस्थान जन-आधार योजना** और राज्य में पहली बार विराट सफलता के साथ आयोजित हुए राज्य खेल, इनके उदाहरण हैं। हमने इस बजट में भी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

- अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सम्पूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है और इस परिवार के लिए मैं, **सात संकल्पों** को इस बजट की प्राथमिकताएं बनाना चाहता हूँ :-

पहला संकल्प - **निरोगी राजस्थान**

दूसरा संकल्प - **संपन्न किसान**

तीसरा संकल्प - **महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण**

चौथा संकल्प - **सक्षम मजदूर, छात्रा-युवा-जवान**

पांचवां संकल्प - **शिक्षा का परिधान**

छठा संकल्प - **पानी, बिजली व सड़कों का मान**

सातवां संकल्प - **कौशल व तकनीक प्रधान**

पहला संकल्प– निरोगी राजस्थान

'पहला सुख–निरोगी काया' की हमारी सदियों पुरानी मान्यता को आगे रखते हुए हम, यह बजट स्वस्थ राजस्थान को समर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा असली धन है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं । निरोगी राजस्थान के प्रथम संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कार्ययोजना सदन के सामने रखी जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में हमने कुल 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
- प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, जनता क्लिनिक, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाएं हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में, हमने दिसंबर, 2019 से **निरोगी राजस्थान** अभियान प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि बीमारियों के prevention पर फोकस किया जाये। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए मैं, **100 करोड़ रुपये के 'निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष'** के गठन की घोषणा करता हूँ, जिसके उपयोग के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे। साथ ही, इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपये अभियान प्रबंधन, प्रचार-प्रसार, परिचर्चा एवं गोष्ठियों के आयोजन हेतु दिये जायेंगे।
- जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त प्रांतवासियों को निरोगी रहने के लिए सही जीवनशैली अपनाने में सक्षम करना ही हमारे इस अभियान का मूल मंत्र है। अगले वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान के नागरिकों का digital health survey किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, राज्य में समय पर नि:शक्तता की पहचान के लिए सरकार, जिला स्तर पर Early Intervention Centre की स्थापना करेगी, जिससे समय पर इलाज प्रारंभ हो सके।
- राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तथा वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके इस हेतु, मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम उठाये जायेंगे, जिसके तहत पृथक् से एक **ऑथोरिटी** के गठन की घोषणा करता हूँ ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में लैब का भी गठन किया जायेगा, जिसमें नमूने की रिपोर्ट online दी जायेगी। साथ ही, मिलावटखोरों के विरूद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु अलग से Fast Track Courts स्थापित की जायेंगी।
- हमारे द्वारा प्रारंभ की गयी नि:शुल्क दवा योजना एवं नि:शुल्क जांच योजना ने देशभर में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनकी सराहना देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई है। प्रदेश के सम्पूर्ण चिकित्सा परिवार के लिए यह सम्मान की बात है। इसके लिए मैं राज्य के सभी चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, फार्मासिस्टों एवं संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। साथ ही, आह्वान करता हूँ कि वे इस बजट के हमारे पहले संकल्प 'निरोगी राजस्थान' के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दें।
- पीपाड़ सिटी एवं फलोदी के राजकीय अस्पताल को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जायेगा। राजकीय चिकित्सालय, औसियां में मदर एण्ड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जायेगा। साथ ही, सांचौर जिला जालौर, तारानगर जिला चूरू, सोजत जिला पाली, लोहावट, बालेसर एवं भोपालगढ़ जिला जोधपुर के राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर खोले जायेंगे।
- हाल ही में हमने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी एवं लीवर की दवाइयों को भी शामिल कर नि:शुल्क दवाइयों की संख्या 709 कर दी है। राज्य में कैंसर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए Cancer Registry System प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें राजकीय एवं निजी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का पंजीयन अनिवार्य होगा, जिससे भविष्य में कैंसर रोगियों को इलाज हेतु उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा।
- राज्य में जहां भी पीपीपी मोड संभव होगा, वहां के जिला चिकित्सालयों में MRI / CT-Scan सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके साथ ही जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु PET CT Scan मशीन उपलब्ध करवाई जायेगी।
- राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में डेन्टल चेयर विद एक्स-रे मशीन की स्थापना की जायेगी, इनके संचालन के लिए पृथक से गाइड लाइन जारी की जायेगी।
- प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नये Sub-Centre, PHC, CHC खोलने अथवा इनके क्रमोन्नयन के लिए criteria तय किया जायेगा। भविष्य में चिकित्सा संस्थान criteria के आधार पर खोले अथवा क्रमोन्नत किये जायेंगे, जिससे निरोगी राजस्थान कार्यक्रम को मजबूती मिले और डॉक्टर व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

- प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में, कुल 1 हजार बेड बढ़ाये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।

चिकित्सा शिक्षा

- गत बजट में मैंने श्रीगंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ में नवीन मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी। यह बताते हुए खुशी है कि उक्त 6 मेडिकल कॉलेज सहित कुल 15 नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। अगले 4 वर्षों में इन कॉलेजों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा, जिस पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें केन्द्र सरकार की 60 प्रतिशत भागीदारी लगभग 3 हजार करोड़ रुपये व राज्य सरकार की 40 प्रतिशत भागीदारी लगभग 2 हजार करोड़ रुपये होगी।
- मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि राज्य का पहला एवं दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट SMS Hospital, Jaipur में किया गया है। इसके लिए मैं चिकित्सकों की टीम को बधाई देता हूँ। वर्तमान में SMS Hospital, Jaipur एवं मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत हैं। साथ ही, अब उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों को Organ Retrieval Centre के रूप में विकसित एवं अधिसूचित किया जायेगा।
- सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रारंभ करने के लिए गेस्ट्रोसर्जरी विभाग की स्थापना की जायेगी। इसके लिए Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi के साथ MoU किया जा चुका है। साथ ही, आगामी वर्ष में यहां अंग प्रत्यारोपण विभाग भी प्रारंभ किया जायेगा, जिसके लिए सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी (Gastroenterology) के सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में जूनियर रेजिडेंट के 69 पदों को सीनियर रेजिडेंट में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में गत वर्ष कैथलैब की स्थापना की गयी थी। आगामी वर्ष में यहां पिडियाट्रिक कैथलैब की स्थापना की जायेगी।
- SMS Hospital, Jaipur में वर्तमान कॉटेज वार्ड के स्थान पर . G+8 मंजिला नया आईपीडी भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इस भवन में कॉटेज वार्ड के साथ-साथ सामान्य वार्ड सुविधा विकसित की जायेगी। दो वर्ष में पूर्ण होने वाले इस कार्य पर 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में न्यूक्लीयर मेडिसिन विभाग की स्थापना की जायेगी। इस पर दो वर्षों में 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, ब्रेन ट्यूमर सेरिब्रल एन्जियोग्राफी एवं stenting के रोगियों के ईलाज के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से DSA (Digital Subtraction Angiography) मशीन स्थापित की जायेगी।

चिकित्सा

नि:शुल्क दवा योजना एवं नि:शुल्क जांच योजना ने देशभर में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनकी सराहना देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई है। मैं आह्वान करता हूँ कि वे इस बजट के हमारे पहले संकल्प 'निरोगी राजस्थान' के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दें।

- जयपुर में कैंसर के उपचार के लिए उच्च श्रेणी का अस्पताल **राज्य कैंसर संस्थान** बनकर तैयार है, इसमें हाल ही में ओपीडी प्रारंभ कर दिया गया है। इसे अगले वित्तीय वर्ष में संपूर्ण आधुनिक उपकरणों यथा लीनियर एक्सीलेटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर के साथ सुचारू रूप से चलाया जायेगा। इस संस्थान के बेहतर प्रबंधन के लिए सहायक आचार्य मेडिकल ऑन्कोलॉजी के 3, सहायक आचार्य रेडियोलोजी के 2 एवं सहायक आचार्य Dental and Prosthetics Head and Neck Cancer Surgery का एक पद सृजित किया जायेगा।
- मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के OPD ब्लॉक के शेष लोर का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी अस्पताल में 30-30 बेड के 4 नये वार्ड खोले जायेंगे, जिस पर लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक नया न्यूरो इंटरवेंशन लैब भी बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यहां क्षेत्रीय कैंसर सेंटर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

आयुर्वेद

- वर्तमान में प्रदेश में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है। अत: अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 18 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है।
- सीकर जिला मुख्यालय पर 50 शैय्याओं के एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। इस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नवीन पीजी महिला छात्रावास एवं वर्तमान स्नातक छात्रावास का निर्माण/विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

दूसरा संकल्प–संपन्न किसान

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट में 1 हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की थी, जिसे दिसंबर, 2019 में स्थापित कर दिया गया है।

कृषि

- वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग के लिए कुल 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में कृषि के लिए भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल-संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। वर्षा जल को संगृहीत कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में 12 हजार 500 फार्म पौण्डों का निर्माण करवाया जायेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- राज्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जायेगा, जिसके लिए 91 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- राजस्थान, कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम है। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 25 हजार सोलर पंप लगाये जायेंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- वर्ष 2020-21 में 2 लाख टन यूरिया तथा 1 लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- उन्नत बीज की मांग को देखते हुए राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन 8 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 12 लाख क्विंटल किया जायेगा। साथ ही, निगम के बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए 200 मण्डी प्रांगणों में चरणबद्ध रूप से नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझान तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, सिरोही एवं झुंझुनूं आदि जिलों के 1 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा।
- प्रदेश में किसानों को किराये पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए KVSS / GSS के माध्यम से मांग के अनुसार 100 **कस्टम हायरिंग** केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इस पर 8 करोड़ रुपये का खर्च होगा।
- किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए चरणबद्ध रूप से 44 नई स्वतंत्र मण्डियां पिड़ावा, डग, मनोहरथाना जिला झालावाड़; पूंगल रोड-बीकानेर; कुशलगढ़-बांसवाड़ा; छीपाबडौद, नाहरगढ एवं समरानिया जिला बारां; चौहटन, धोरीमन्ना एवं गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर; करौली; डूंगला-चित्तौड़गढ़; डबली राठान, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़; कुम्हेर, पहाड़ी, भुसावर एवं रूपवास जिला भरतपुर; सोजत सिटी-पाली; अरनोद व धरियावद जिला प्रतापगढ; बींझबायला-श्रीगंगानगर; देवगढ़-राजसमन्द; खण्डार-सवाई माधोपुर; सलूंबर-उदयपुर; बगरू, सांगानेर, शाहपुरा जिला जयपुर; मथानियां-जोधपुर; मोहनगढ़ व रामगढ़ जिला जैसलमेर; जायल व खींवसर जिला नागौर; टोडारायसिंह-टोंक; गुलाबपुरा-भीलवाड़ा; किशनगढ़बास, बहरोड, तिजारा, गोविन्दगढ, अलवर (फ.स.), रामगढ़ एवं बानसूर जिला अलवर एवं सांगोद-कोटा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, 100 नवीन गौण उपज मंडी समितियों की भी स्थापना जायेगी। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में भी मंडियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन एक नये डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जायेगी, इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।

कृषि

खजूर की खेती के प्रति बढ़ते रुझान तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, सिरोही एवं झुंझुनूं आदि जिलों के 1 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा।

- किसानों की आय में वृद्धि, विपणन व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन, कृषि को जोखिम रहित बनाने, किसान एवं खरीददार के मध्य लाभकारी व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से दो नवीन अधिनियम 'राजस्थान राज्य कृषि उपज (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020' एवं 'राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती एवं सेवायें (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020' लाये जा रहे हैं।

सहकारिता

- हमारी सरकार के द्वारा फसली ऋणों में पारदर्शिता लाने एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से बांटे जाने वाले फसली ऋणों के वितरण के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना-2019 लागू की गई है, जिसके तहत अब तक सहकारी बैंकों के द्वारा 22 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के फलस्वरूप अब तक सहकारी बैंकों के फसली ऋण से 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1 हजार 800 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है।
- वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- राज्य में आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2 हजार नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स/लैम्प्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जायेगा।
- वर्ष 2020-21 में राज्य के चयनित GSS, KVSS और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम बनाये जायेंगे, जिन पर 22 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

पशुपालन

- प्रदेश में अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सोर्टेड सीमन (Sexed Sorted Semen) के उपयोग की योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस तकनीक के उपयोग से बछड़ों के बजाय बछड़ियों के पैदा होने की सम्भावना अधिक रहती है। परियोजना पर 10 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।
- पशुपालकों को नवीन तकनीकों एवं प्रबन्धन की जानकारी देने हेतु 4 हजार पशुपालकों को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- पशु चिकित्सालय रातानाड़ा-जोधपुर के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

तीसरा संकल्प

महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण

गत वर्ष हमारे द्वारा घोषित 1 हजार करोड़ रुपये की **'इंदिरा महिला शक्ति निधि'** के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक रचनात्मक पहल की गई। इस वर्ष महिला, बालकों एवं वृद्धजनों के हितार्थ लिए गये तीसरे संकल्प के तहत किये जाने वाले कार्य सदन के समक्ष रखे जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास

- एक ही क्षेत्र में अलग-अलग स्तर पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय तथा कन्वर्जेंस के लिए कॉमन प्लेटफार्म 'A-3 (Aanganwadi worker, Asha Sahyogini, ANM) एप' विकसित किया जायेगा। इससे न केवल इनके मध्य बेहतर समन्वय होगा, अपितु लाभार्थियों को भी समय पर समुचित सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथिनों के प्रशिक्षण हेतु एचसीएम रीपा, जयपुर व राज्य में स्थित अन्य राजकीय संस्थानों के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी। साथ ही, एचसीएम रीपा, जयपुर में 'इन्दिरा गांधी महिला शोध संस्थान' भी स्थापित किया जायेगा।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि से पोषाहार वितरित किया जाता है। इसमें पारदर्शिता लाने हेतु पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसमें विविधता लाने की कार्यवाही की जायेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- हमारी सरकार द्वारा EWS को दिये जाने वाले आरक्षण की पात्रता की अव्यावहारिक शर्तों एवं प्रक्रिया को हटाकर सिर्फ 8 लाख रुपये वार्षिक आय की शर्त रखने का प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों (Economically Backward Class) के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने हेतु मैं, **'राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड'** के गठन की घोषणा करता हूँ।

- आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में वर्तमान में 4 लाख 22 हजार से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिस पर अगले वर्ष लगभग 450 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। पालनहार योजना के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए, गत वर्ष जयपुर में एक पालनहार छात्रावास की घोषणा की गयी थी। इसे आगे बढ़ाते हुए अब प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास (हाफ-वे-होम) खोला जायेगा।
- बालक प्रदेश के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन हैं। सरकार का दायित्व है कि हर बच्चे को सभी बाल अधिकार, खासकर बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिलें। इसके लिए, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरु आज भी बच्चे जिन्हें चाचा नेहरु कहते हैं, के नाम से **100 करोड़ रुपये** के **'नेहरु बाल संरक्षण कोष'** के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया जा सकेगा।
- कई बार जन्म के समय बच्चों में बहरेपन की पहचान नहीं हो पाती है, जिससे आरंभिक अवस्था में उनका इलाज नहीं हो पाता। इस कारण से वे पूरे जीवन मूक बधिर ही रहते हैं। हालांकि कॉकलीयर इम्प्लांट के रूप में इस समस्या का निदान संभव है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से 5 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर 96 बच्चों को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक 899 बच्चों हेतु 44 करोड़ 52 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है, जहां पर सरकारी खर्च से कॉकलीयर इम्प्लांट करने शुरू किये गये। इस योजना को अब केन्द्र सरकार द्वारा भी पूरे भारत में लागू किया गया है। अब हम अगली कड़ी में, बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही hearing screening की अनिवार्यता हेतु नीति बनाकर लागू करेंगे।
- गत वर्ष हमारे द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों को देय मैस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की गयी थी। इस वर्ष शेष अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम, भिक्षावृत्ति वाले प्रस्तावित आवासीय संस्थानों में भी प्रति आवासी यह राशि 2 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की जायेगी।
- 'राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड' के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 25 हजार युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगामी वर्ष इनकी संख्या बढ़ाते हुए 50 हजार युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

अल्पसंख्यक

- अजमेर जिले के मसूदा एवं भरतपुर जिले के कामां ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपयों की लागत से अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर एवं लाडनूं-नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत आयेगी।
- जिला मुख्यालय जयपुर में 100 शैय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जायेगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- राजस्थान वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट उपलब्ध करवायी जायेगी।

जनजाति विकास

- TSP Area के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 5 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 15 हजार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- TSP Area में खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पारडा चुण्डावत जिला डूंगरपुर, पाडोला जिला बांसवाड़ा, टीमरवा जिला प्रतापगढ़, हनौतिया जिला बारां के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1 हजार 530 से बढ़ाकर 2 हजार 400 किया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के लिए पृथक कैडर बनाया जायेगा।
- कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पम्प स्थापना हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30-30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। TSP क्षेत्र के जनजाति किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45 हजार रुपये प्रत्येक कृषक को, अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करवाये जाकर 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाले जनजाति परिवारों को वन भूमि के अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन, सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, बकरी पालन इत्यादि हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। इससे TSP Area के लगभग 14 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

चौथा संकल्प

सक्षम मजदूर, छात्र–युवा–जवान

राज्य के ऊर्जावान युवाओं एवं मेहनतकश मजदूरों के लिए चौथे संकल्प के रूप में हमने आगामी वर्ष के लिए विस्तृत रूपरेखा बनायी है। हमारी विशेष कोशिश खेलों के क्षेत्र में राज्य को तेजी से आगे लाने की रहेगी।

युवा मामले एवं खेल

- हाल ही में सम्पन्न हुई **राज्य खेल प्रतियोगिता** जिसमें 18 खेलों के लगभग 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया, की तारीफ चारों ओर हो रही है। पहली बार संपन्न हुए इन खेलों का ही नतीजा था कि असम में हुए 'खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2020' में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। खेलों के प्रति जागरुकता लाकर हम Fit Rajasthan, Hit Rajasthan के लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ायेंगे।
- ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर हम ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करेंगे। जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल और अधिक सफल हो सकेंगे। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जायेगा।
- इस वर्ष आयोजित राज्य खेलों में क्रिकेट और हैण्डबाल शामिल नहीं किये जा सके थे। अब इन खेलों के भी ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरीय आयोजन करवाये जायेंगे।
- मैं, प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपये की इनामी राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही राशि 50 लाख रुपये को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही राशि 30 लाख रुपये को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। उसी तरह एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही राशि 30 लाख रुपये को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही राशि 20 लाख रुपये को बढ़ाकर 60 लाख रुपये एवं कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही राशि 10 लाख रुपये को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं।
- प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाये जायेंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा।
- राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमश: 500 से 1 हजार रुपये एवं 300 से 600 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

उद्योग

- प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए **राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019** जारी की गई है। इसी क्रम में, **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019** भी लागू की गई है। क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की दृष्टि से अधिघोषित Most Backward Areas में स्थापित होने वाली पात्र इकाइयों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी रखा जायेगा।
- प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए सभी अनुमतियां एक ही स्थान से प्रदान कराने के लिए हमारे द्वारा वर्ष 2011 में **सिंगल विंडो एक्ट** लागू किया गया था। इस एक्ट की अनुपालना को और प्रभावी बनाने के लिए **'वन स्टॉप शॉप'** प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 'बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट' का गठन किया जायेगा। यह बोर्ड निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ ही, प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों को BIP में प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जिससे निवेश प्रस्तावों को त्वरित clearances मिल सकेगी।
- अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं रोजगार सृजन में MSME उद्योगों की महत्ती भूमिका है। राज्य में MSMEs की आसानी से स्थापना हेतु हम वर्ष 2019 में नया एक्ट लेकर आये और पहले तीन सालों तक इन्हें समस्त सरकारी स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों की बाध्यता से मुक्त किया। इसमें online रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अब तक 3 हजार 339 उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तथा उनको तत्काल सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों की सुविधा के लिए **'राज उद्योग मित्र पोर्टल'** प्रारंभ किया गया है।

उद्योग

राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रीको इकाई कार्यालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त हिण्डौन जिला करौली एवं गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जायेगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जायेगा।

- देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केन्द्र जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का 'राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो' आयोजित किया जायेगा। इसके आयोजन में अनुमानित व्यय 3 करोड़ रुपये का होगा, जो रीको द्वारा वहन किया जायेगा।
- राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर,बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रीको इकाई कार्यालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त हिण्डोन जिला करौली एवं गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जायेगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जायेगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र-2 सीतापुरा, जयपुर में करीब 25 हजार वर्गफीट पर plug and play facility का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस facility में छोटे तथा अन्य उद्योगों को ready to more built-up area उपलब्ध करवाया जायेगा, जिससे वह अपनी इकाई, कम से कम समय में शुरू कर सकेंगे।
- प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं आयातकों-निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प एम्पोरियमों, इनलेण्ड कंटेनर डिपो और एयरकार्गो का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण करवाया जायेगा।

गांधी स्मृति

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर जयपुर में **खादी प्लाजा** की स्थापना की जायेगी। इस पर 10 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत की छूट देने से खादी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है, इसलिए अब राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्तपोषित राज्य की 144 खादी संस्था/समितियों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सभी खादी संस्था/समितियों के कार्यों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे वे अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, बुनकर संघ का भी सुदृढ़ीकरण करवाया जायेगा। इस हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

पेट्रोलियम एवं खनिज

- प्रदेश में पारदर्शिता के साथ खान आवंटन करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कम से कम दो हजार हैक्टेयर प्रधान खनिज एवं एक हजार हैक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई-ऑक्शन हेतु उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर हमारी सरकार का focus है। इस परियोजना की कुल लागत 43 हजार 129 करोड़ रुपये है। इस हेतु गठित HPCL Rajasthan Refinery Ltd. कंपनी में HPCL की 74 प्रतिशत एवं राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत भागीदारी है। इस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम HPCL से नियमित follow up एवं समन्वय करके जल्दी से जल्दी रिफाइनरी निर्माण कार्य को पूर्ण करवायें।
- राज्य में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्वेषण (Exploration) की गतिविधियां बढ़ानी होंगी। हमने 10 Petroleum Exploration Licence (PET) किये हैं एवं आगामी वर्ष में 3 PEL और स्वीकृत किये जायेंगे। अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से संपादित करने के लिए बाड़मेर जिले में उप निदेशक (पेट्रोलियम) कार्यालय खोला जायेगा तथा विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी।
- माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य में लगभग 2 हजार 476 मिलियन टन पोटाश अयस्क के भंडार की संभावना है। वर्तमान में हमारा देश पोटाश के लिए पूर्णतया आयात पर निर्भर है।

यह बहुमूल्य खनिज पूरे देश में सिर्फ हमारे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले सहित कुछ क्षेत्र में उपलब्ध है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्वेषण व फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

- रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर व पचपदरा जिला बाड़मेर में Hydrocarbon Sector की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कौशल केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

- राज्य में 57 नई पंचायत समितियों एवं 1 हजार 456 नई ग्राम पंचायतों के गठन के उपरान्त जिन ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन कार्यालय प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं हैं, उनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे हमारी सरकार ने पूर्व में गंभीरता से लागू किया था। लेकिन, विगत कुछ सालों में इस योजना के क्रियान्वयन में कई कमियां नजर आई हैं। हमारी सरकार ने नरेगा योजना को पुन: मजबूत बनाने के लिए **काम मांगो अभियान** के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाई है। इस वर्ष अब तक 53 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिनमें से लगभग 4 लाख 87 हजार परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है। योजना पर इस साल अब तक लगभग 6 हजार 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

पर्यटन

- देश में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान सिरमौर रहा है। मैं, पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु **100 करोड़ रुपये** के **पर्यटन विकास कोष** के गठन की घोषणा करता हूँ। इस कोष के उपयोग हेतु पृथक् से रूपरेखा तैयार की जायेगी। साथ ही, राज्य में 'Ease of Travelling in Raja sthan' की नीति विकसित की जायेगी।
- RTDC की 4 हेरिटेज संपत्तियों लेक पैलेस सिलीसेढ़-अलवर, झूमर बावड़ी रणथम्भौर-सवाईमाधोपुर, गोकुल नाथद्वारा-राजसमन्द एवं होटल सरोवर पुष्कर-अजमेर के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- आगामी वर्ष में 1 हजार राज्य स्तरीय एवं 5 हजार स्थानीय स्तर के गाइडों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे कि उन्हें गाइड लाइसेंस प्रदान किये जा सकें।

पांचवां संकल्प
शिक्षा का परिधान

प्रदेश के अच्छे कल के लिए हमें विद्यार्थियों को बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना होगा। अच्छी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार हो सकता है और ये ही हमारा 5वां संकल्प है।

शिक्षा

- शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
- प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से English Medium राजकीय विद्यालयों का प्रयोग काफी सफल रहा है। राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर English Medium विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अत: अब, शेष 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक English Medium महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- Right to Education के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर सीनियर हायर सैकंडरी तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित gap को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकंडरी विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।
- प्रदेश के 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे, जिन पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- एक सकारात्मक पहल करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन **No Bag Day** रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक-

शिक्षा

प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से English Medium राजकीय विद्यालयों का प्रयोग काफी सफल रहा है। राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर English Medium विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अत: अब, शेष 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक English Medium महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यापक (Parent-Teacher) मीटिंग के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काउट, जीवनमूल्य एवं नैतिक शिक्षा, बालसभायें तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियायें संपादित करवायी जायेंगी, जिनमें अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा।

- राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, छात्रावास, बैडमिंटन कोर्ट, स्वीमिंगपूल, ऑडिटोरियम आदि सुविधाएं विकसित की जायेंगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।
- राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए नये **'कम्प्यूटर शिक्षक कैडर'** का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें 38 हजार 700 बालिकायें अध्ययनरत हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। प्रथम चरण में 22 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे, जिनमें से 12 विद्यालय तलवाड़ा, अर्थुना, गांगड़ तलाई एवं छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा, पाटोदी एवं शिव जिला बाड़मेर, गलियाकोट जिला डूंगरपुर, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, कुरावड़, लसाड़िया, झल्लारा एवं ऋषभदेव जिला उदयपुर के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में खोले जायेंगे। शेष 10 विद्यालय मण्डरायल जिला करौली, धनाउ जिला बाड़मेर, बिदासर जिला चूरू, बिजोलिया जिला भीलवाड़ा, नोहर एवं भादरा जिला हनुमानगढ़, सुल्तानपुर जिला कोटा, बांदीकुई जिला दौसा, खानपुर जिला झालावाड़ तथा आमेर जिला जयपुर में खोले जायेंगे।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

- महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास हेतु Skil Enhancement & Employable Training (SEET) कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रति वर्ष 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक की स्थापना की जायेगी, जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिये गये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जायेगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवायी जाती रहेगी।
- पिछले बजट में हमने राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु नीति बनाने की घोषणा की थी। यह नीति जारी की जा चुकी है। गत वर्ष घोषित महाविद्यालयों में आवश्यक स्टाफ एवं भवन की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में प्राप्त मांगों पर जारी नीति अनुरूप कॉलेज खोलने का उचित निर्णय भविष्य में लिया जायेगा।
- प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाईनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के प्रथम MBM Engineering College को upgrade करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।

शिक्षा

प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक की स्थापना की जायेगी, जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिये गये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जायेगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवायी जाती रहेगी।

छठा संकल्प
पानी, बिजली व सड़कों का मान

राज्य सरकार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विद्युत आपूर्ति की निरंतरता एवं अच्छी सड़कें उपलब्ध करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमने यह छठा संकल्प लिया है।

पेयजल

- PHED के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। इस हेतु भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है, के माध्यम से हर घर में जल पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में सीमित जल संसाधन होने तथा बड़ा भूभाग मरूस्थलीय होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा केवल 50 प्रतिशत राशि ही राज्य को उपलब्ध करवायी जा रही है, जबकि केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत एवं पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्यों में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थतियों को देखते हुए केन्द्र सरकार से उनकी हिस्सा राशि 90 प्रतिशत करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।
- पूरे प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में प्रथम चरण में वर्ष 2020-21 में 16 जिलों झुंझुनूं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, बारां, अजमेर, कोटा, बूंदी एवं करौली की 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। इससे 4 हजार 327 गांवों एवं 9 हजार 159 ढाणियों के लगभग 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। इन कार्यों पर लगभग 1 हजार 350 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है।
- वर्ष 2020-21 में 4 हजार से कम आबादी वाले 250 गांव जहां पेयजल स्रोत उपलब्ध हों, में नवीन सेवा स्तर मापदण्ड अनुसार, नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के कुल 625 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इससे लगभग 1 लाख 10 हजार घर लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 160 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है।
- प्रदेश में 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को मापदण्ड अनुसार, पेयजल से लाभान्वित करने हेतु कुल 750 करोड़ रुपये के पुनर्गठन कार्य हाथ में लिये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है।
- वर्ष 2019-20 में चम्बल भीलवाड़ा के आरोली Water Treatment Plant से जोड़कर बूंदी जिले के हिंडौली सहित शेष रहे क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने हेतु घोषित की गयी DPR बन गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 970 करोड़ रुपये की इस परियोजना को शुरू कर बूंदी जिले के 286 गांवों, 287 ढाणियों एवं नैनवा कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा।
- जयपुर शहर में चारदीवारी एवं आस-पास के क्षेत्र में उचित दवाब से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जिसके तहत 5 उच्च जलाशयों के निर्माण के साथ नई मुख्य वितरण लाइन एवं पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने का कार्य किया जायेगा। इस योजना पर 165 करोड़ रुपये का व्यय कर 9 लाख की आबादी को लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नये स्रोत का निर्माण, स्वच्छ जलाशय का निर्माण, राइजिंग तथा वितरण पाइपलाइन इत्यादि कार्य कर पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जायेगा। इस योजना पर 15 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
- गत वर्ष राजसमन्द जिले के भीम क्षेत्रा हेतु भीलवाड़ा जिले की चंबल पेयजल परियोजना से पानी पहुंचाने की योजना का परीक्षण करने की घोषणा की थी। अब परीक्षण उपरांत इस कार्य हेतु आगामी वर्ष में DPR बनायी जायेगी। किया जायेगा।

ऊर्जा

- ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए गत वर्ष के बजट भाषण में नवीन सौर एवं पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में हमारे द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गयी है।
- नई सौर ऊर्जा नीति में हमने चरणबद्ध रूप से 30 हजार मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित

ऊर्जा

राज्य में अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हम रूफटॉप सोलर सिस्टम को वृहद् पैमाने पर लागू करेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को **'ग्रीन एनर्जी सिटी'** के रूप में विकसित किया जायेगा।

किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निजी निवेशकों के साथ-साथ केन्द्रीय राजकीय उपक्रमों के माध्यम से भी अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

- थर्मल पावर प्लांट में कोयले की बचत एवं प्रदूषण में कमी करने के लिए इन प्लांटों से उत्पादित ऊर्जा में सौर ऊर्जा मिश्रित कर विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना थर्मल पावर प्लांट के परिसर में उपलब्ध भूमि पर करने की योजना बनायी जाकर मूर्तरूप दिया जायेगा।
- राज्य में अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हम रूफटॉप सोलर सिस्टम को वृहद् पैमाने पर लागू करेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को **'ग्रीन एनर्जी सिटी'** के रूप में विकसित किया जायेगा। इस क्रम में आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल योजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने एवं निर्बाध संचालन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 पेयजल परियोजनाओं को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर में convert किया जायेगा।
- इस वर्ष 1 लाख 31 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सभी श्रेणी तथा बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति सहित कुल 50 हजार कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किये जायेंगे।
- प्रदेश के सभी किसान भाइयों को खेती के लिए रात्रि में बिजली उपलब्ध करवाये जाने से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। भरी ठंड में रात में खेतों में काम करना बेहद कठिन कार्य है। सरकार किसानों की इस पीड़ा को दूर करना चाहती है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में दिन के दो ब्लॉक में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवायी जायेगी। इसके लिए विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।
- इस क्रम में प्रथम चरण में 1 अप्रैल, 2021 तक अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर एवं द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल, 2022 तक सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर तथा तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल, 2023 तक शेष जिलों बाड़मेर, अलवर, दौसा, नागौर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के सभी ग्रामीण फीडरों पर दिन के ही ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति के लिए, तंत्र को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु आगामी तीन वर्षों में 220 केवी के 6 नये जीएसएस, 132 केवी के 30 नये जीएसएस की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त, 33 केवी के 287 नये सब-स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, 1 हजार 500 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त व्यवस्था से 3 वर्ष में राज्य के सभी किसानों को दिन के दो ब्लॉक में कृषि हेतु विद्युत उपलब्ध करवायी जा सकेगी। ***जिस पर लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।***
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रथम वर्ष 2020-21 में 220 केवी के 3 जीएसएस अकलेरा जिला झालावाड़, रावतसर जिला हनुमानगढ़ में नये तथा छतरगढ़ जिला बीकानेर में, क्षमतावृद्धि पश्चात् कमीशन किये जायेंगे। इसके साथ ही, 132 केवी के 9 नये जीएसएस नाहरगढ़ जिला बारां, चौरड़ी जिला बांसवाड़ा, बालेर जिला सवाईमाधोपुर, नेगाडिया दानपुर जिला बांसवाड़ा, मोहनगढ़ व झिनझिनयाली जिला जैसलमेर, टिब्बी जिला हनुमानगढ़, जेरण जिला जालौर, करौली जिला अलवर कमीशन किये जायेंगे।
- इस वर्ष चांदेरा तहसील सिकराय, अड्डा पंचायत समिति बयाना, भैंसिना पंचायत समिति वैर, दिवली पंचायत समिति वैर, मोलोनी पंचायत समिति वैर, निवाई पीपलू का झिराना बड़गांव, बेंगू तहसील में जोगणिया माता, तहसील गंगरार में मंडपिया, डीडवाना में खोजास एवं बरागना, करौली में पेंटोली एवं शेरपुर में 33 केवी के नये सब-स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

सार्वजनिक निर्माण

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 6 हजार 808 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से प्रथम चरण में निम्न क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में किया जायेगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यय होगा:-

निम्बाहेड़ा-केली-कनेरा-बस्सी-आंबा रोड का चौड़ाईकरण जिला चित्तौड़गढ़	37 करोड़ 50 लाख रुपये
सीमलवाड़ा-मांडली-धंबोला-जोगपुर सड़क जिला डूंगरपुर	19 करोड़ 26 लाख रुपये
मांगरोल से अंता वाया पंचेल कला सड़क का चौड़ाईकरण जिला बारां	49 करोड़ 94 लाख रुपये
जोधपुर से बनाड़ एवं अन्य सड़कें तथा जोधपुर जिले में डांगियावास-गुडा- कांकाणी-धुन्धाडा-समदड़ी	59 करोड़ रुपये
टोंक शहर की विभिन्न सड़कें 30 करोड़ रुपये मलाराना डूंगर से सांखड़ा जिला सवाई माधोपुर	12 करोड़ रुपये
भरतपुर से सौंख सड़क जिला भरतपुर	18 करोड़ रुपये
चूरू तारानगर सड़क (चौड़ाईकरण) जिला चूरू	16 करोड़ रुपये
झालावाड़ में सुलिया-सुनेल-पिड़ावा-सोयत सड़क (मध्य प्रदेश सीमा तक)	10 करोड़ रुपये
प्रतापगढ़ से मंदसौर सीमा तक	7 करोड़ 50 लाख रुपये
गोगुन्दा-तुला-मचिन्द-गांवगुड़ा-सांगठ राजसमन्द सड़क	40 करोड़ रुपये
NH-52 मोदी विश्वविद्यालय से बड़काबालाजी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	5 करोड़ रुपये
पुष्कर से केकड़ी जिला अजमेर	75 लाख रुपये
बांसवाड़ा जिले में संपर्क सड़क देवका	4 करोड़ रुपये
बाड़मेर जिले में जालीपा-हरसाणी	3 करोड़ रुपये
दौसा-कुंडल-बांदीकुई-कठूमर जिला दौसा	5 करोड़ रुपये
बूंदी-अलोद-मेण्डी सड़क जिला बूंदी	20 करोड़ रुपये
विराट नगर जयपुर से चिलपाली मोड वाया पालड़ी तिराहा	30 करोड़ रुपये
बीकानेर शहर की सड़कें	7 करोड़ 50 लाख रुपये

उक्त सड़कें राज्य की सर्वाधिक क्षतिग्रस्त स्थिति की हैं, जिनको प्रथम चरण में लिया गया है। शेष जिलों की इस तरह की क्षतिग्रस्त सड़कों के कार्य द्वितीय चरण में किये जायेंगे।

- प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम व द्वितीय फेज का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के फेज तृतीय में मार्च, 2025 तक राज्य की 8 हजार 663 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग 4 हजार 245 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन करवाया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन

- प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के तुरन्त बाद नजदीकी निजी अस्पताल में ले जाये जाने पर, ऐसे निजी अस्पताल द्वारा उसका उपचार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की सकेगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो आवश्यक कानूनी प्रावधान भी किये जायेंगे। इसके लिए पृथक् से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

- परिवार में असमय हुई मृत्यु मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक आघात लाती है। राज्य में हर साल लगभग 10 हजार 500 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हो जाते हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी कैसे हो, इसके लिए हमारी टीम तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करके आयी है। तमिलनाडु, सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 30 प्रतिशत की कमी लाकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है। हम सब मिलकर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए तमिलनाडु की तर्ज पर रोड मैप तैयार किया जायेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी यातायात एवं संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी वर्ष में दो बार स्थिति की समीक्षा करेगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

- राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले सर्वश्रेष्ठ तीन जिलों को क्रमश: 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये का **'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार'** दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राज्य के 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Primary Trauma Centre के रूप में विकसित किया जायेगा, जिस पर 10 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

- आमजन की सुविधा के लिए समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र की तर्ज पर लाइसेन्स एवं पंजीयन सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के माध्यम से Front Office Management System संचालित किये जायेंगे।

- जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

- छात्रा-छात्राओं एवं आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक एवं शिक्षित करने के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में **ट्रैफिक पार्क**

स्थापित किये जायेंगे, जिस पर 16 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास

- जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 4 हजार 557 करोड़ 87 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project-ERCP) को सिंचाई एवं जलदाय के लिए top priority में सम्मिलित करने का निश्चय किया जा रहा है। यह योजना राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर के लिए पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से अतिमहत्त्वपूर्ण है, जिसकी अनुमानित लागत 37 हजार 247 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पूर्वी जिलों के लिए वैसी ही जीवनदायिनी हो सकती है, जैसी पश्चिमी जिलों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जयपुर एवं अजमेर में इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता देने हेतु आश्वस्त किया था। मैं भी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी को स्मरण करवा चुका हूँ।**
- सरकार **बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP)** के अन्तर्गत आगामी वर्षों में 503 करोड़ रुपये के कार्य करवायेगी। परियोजना के प्रथम चरण में वर्ष 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रारंभ किये जायेंगे, जिसमें बीसलपुर, माही, जवाई, जाखम, सोम कमला अम्बा, छापरवाड़ा, मातृकुण्डिया, गंभीरी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज इत्यादि प्रमुख बांध सम्मिलित हैं।

जल संसाधन एवं सिंचित विकास

राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर के रिलाइनिंग हेतु भारत सरकार व पंजाब सरकार के साथ MoU किया गया है। इसके लिए, मैं जुलाई, 2019 में पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। मुझे खुशी है कि पंजाब द्वारा दिसंबर, 2019 में सरहिन्द फीडर के सर्वाधिक क्षतिग्रस्त लगभग 17 किलोमीटर में रिलाइनिंग का कार्य संपादित करवा दिया गया है।

- राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (RWSRPD) के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर इस वर्ष 245 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, जिससे हनुमानगढ़ जिले के रावतसर, टिब्बी व हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तथा बीकानेर जिले के खाजूवाला तहसील क्षेत्र के काश्तकारों को इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2020 के क्लोजर में सिरसा-हरियाणा, रावतसर, टिब्बी एवं सूरतगढ़ की मुख्य नहरों में तथा सूरतगढ़, अनूपगढ़ व रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी आदि की लगभग 44 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग का कार्य किया जायेगा। आगामी वर्ष में इस पर 378 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर के रिलाइनिंग हेतु भारत सरकार व पंजाब सरकार के साथ MoU किया गया है। इसके लिए, मैं जुलाई, 2019 में पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। मुझे खुशी है कि पंजाब द्वारा दिसंबर, 2019 में सरहिन्द फीडर के सर्वाधिक क्षतिग्रस्त लगभग 17 किलोमीटर में रिलाइनिंग का कार्य संपादित करवा दिया गया है।
- ERCP परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में कालीसिंध नदी के अधिशेष जल को बनास नदी में अपवर्तित करने हेतु 602 करोड़ रुपये की लागत से नवनैरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य से कोटा, बूंदी व बारां जिले को लगभग 54 MCM अतिरिक्त जल पेयजल हेतु उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, शेष अतिरिक्त जल बीसलपुर बांध में अपरिवर्तित किया जा सकेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- भरतपुर जिले के कामां, कुम्हेर एवं डीग क्षेत्रा के काश्तकारों हेतु सिंचाई सुविधा सुदृढ़ करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में गुड़गांव मुख्य नहर की 23 माईनरों के जीर्णोद्धार के कार्य 70 करोड़ रुपये की लागत से कराये जायेंगे।
- सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में बनास नदी पर भारजा नदी ग्राम के पास घोषित एनिकट के कार्य को इस वर्ष हाथ में लिया जायेगा, जिस पर 33 करोड़ रुपये का व्यय होना प्रस्तावित है।
- हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अभी कल ही भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एण्ड पॉवर (CBIP) द्वारा प्रदेश को जल प्रबंधन के क्षेत्र में 2 श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के CBIP Award-2020 से सम्मानित किया गया है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास

- प्रदेश में मण्डावरी जिला दौसा, बस्सी जिला जयपुर, रामगढ़ जिला अलवर, बानसूर जिला अलवर, जायल जिला नागौर एवं भोपालगढ़ जिला जोधपुर में नगरपालिकाओं का गठन प्रस्तावित है।
- प्रदेश के जिन 9 जिला मुख्यालयों सिरोही, जैसलमेर, करौली,

दौसा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर एवं प्रतापगढ़ पर टाउनहॉल नहीं थे, उनमें से इस वर्ष सिरोही एवं जैसलमेर में टाउन हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी क्रम में अगले वर्ष धौलपुर एवं करौली में कुल 30 करोड़ रुपये की लागत से टाउन हॉल बनवाये जायेंगे।

- जोधपुर आज पर्यटन, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए बड़े केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। जोधपुर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के लिए एक आधुनिक बड़े ऑडिटोरियम की कमी महसूस की जा रही है।
- भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन यहां हो सकें, इसे देखते हुए जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में इसकी DPR तैयार करवाई जायेगी। इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- सीवर की सफाई करते हुए कई बार जनहानि होने की घटनायें सामने आती रही हैं। एक सभ्य समाज के लिए यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है। सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुए यह कार्य मशीनों द्वारा किये जाने के लिए सभी निकायों द्वारा सीवर सफाई कार्य एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिए आवश्यक यंत्र एवं उपकरण खरीदे जायेंगे। इस पर कुल 176 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। संबंधित जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मानव को सीवरेज के मैनहोल (गटर) में नहीं उतारा जाये। इस संबंध में शिकायत मिलने पर सम्बन्धित निकाय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
- सीवर ब्लॉकेज के कारण होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए जोधपुर नगर निगम में एक सुपर सकर (Super Sucker) मशीन खरीदी जायेगी, जिस पर लगभग 2 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में RUIDP चतुर्थ चरण के अंतर्गत 7 शहरों आबूरोड, सिरोही, कुचामनसिटी, सरदारशहर, बांसवाड़ा, खेतड़ी एवं मण्डावा में सीवरेज एवं जलप्रदाय के कार्य करवाये जायेंगे। इसके अलावा 6 शहरों रतनगढ़, फतेहपुर, लाडनूं, डीडवाना, मकराना व प्रतापगढ़ में सीवरेज कार्य एवं लक्ष्मणगढ़ शहर में जल प्रदाय कार्य करवाये जायेंगे। इससे 14 शहरों के लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिस पर लगभग 2 हजार 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- जयपुर शहर के सिविल लाइन रेलवे फाटक पर जेडीए द्वारा 75 करोड़ रुपये की लागत से 4 लाइन के RoB का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। पुलिस मेमोरियल से आदर्श नगर होते हुए मनोचिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर, जेडीए एवं ओटीएस चौराहे पर यातायात सुगम बनाने हेतु Feasibility study करवायी जायेगी।

नगरीय विकास

जयपुर शहर के सिविल लाइन रेलवे फाटक पर जेडीए द्वारा 75 करोड़ रुपये की लागत से 4 लाइन के RoB का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। पुलिस मेमोरियल से आदर्श नगर होते हुए मनोचिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर, जेडीए एवं ओटीएस चौराहे पर यातायात सुगम बनाने हेतु Feasibility study करवायी जायेगी।

- JDA द्वारा रामनिवास बाग में दो मंजिलें भूमिगत पार्किंग फेज-2 का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- जोधपुर शहर की जोजरी नदी में साल भर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए तीन STP बनाये जायेंगे।
- आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर, जयपुर में लगभग 65 हजार वर्गमीटर भूमि पर **कोचिंग हब** बनाया जायेगा।
- भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास द्वारा सांगानेर उप नगर को मुख्य शहर से जोड़ने हेतु कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपये की लागत से हाईलेवल ब्रिज बनवाया जायेगा।
- उदयपुर शहर की ऐतिहासिक आयड़ नदी के पुनरूद्धार व सौन्दर्यकरण पर न्यास द्वारा 75 करोड़ रुपये एवं सीवरेज परियोजना, सीसारमा हेतु 8 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। साथ ही, उदयपुर शहर स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं व अन्य कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए नगर विकास न्यास द्वारा अण्टाघर चौराहा, एरोड्रम सर्किल एवं गोबरिया बावड़ी चौराहे पर अण्डरपास का निर्माण कार्य, सिटी मॉल के सामने, आनन्तपुरा तिराहे पर, इंदिरा गांधी तिराहे पर एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा। इन सभी पर लगभग 250 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है।
- कोटा शहर में ऑक्सीजोन (सिटी पार्क) के निर्माण कार्य पर न्यास द्वारा लगभग 100 करोड़ का व्यय किया जायेगा। साथ ही, शहर में चल रहे डेयरी व्यवसायों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना विकसित की जायेगी, जिस पर अनुमानित व्यय 300 करोड़ रुपये का होगा।

सातवां संकल्प
कौशल व तकनीक प्रधान

कौशल एवं रोजगार

- हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम राज्य को Skill एवं IT के तालमेल से physical to digital eco system की ओर ले जायें। इसी क्रम में प्रदेश के समस्त 229 राजकीय ITI में e-Class room के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- विद्यार्थियों में ग्यारहवीं कक्षा से ही उनकी प्रतिभा और अभिरुचि के अनुसार कौशल विकास के लिए **मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना** प्रारंभ की जायेगी।
- Rajiv Gandhi Digital Skill Program के तहत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा युवाओं के लिये राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय (RISU) के सहयोग से emerging new digital technologies जैसे कि Artifical Intelligence, Big Data Analytics एवं Robotics इत्यादि में On-line Digital Skills के कोर्सेज शुरू किये जायेंगे।
- मैं, अप्रवासी राजस्थानी श्रमिक भाइयों के लिए कल्याणकारी योजनायें लागू करवाने हेतु 10 करोड़ रुपये के **प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष** के गठन की घोषणा करता हूँ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

- हमारे द्वारा बड़े reforms के रूप में सरकारी सेवाओं की गारंटीड डिलिवरी के लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 भी लाया गया, परंतु गत सरकार ने इनके implementation पर ध्यान नहीं दिया। अब मुख्य सचिव स्तर पर कमेटी का गठन किया जाकर इन अधिनियमों को सही तरीके से लागू किया जायेगा।
- आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुरूप **जनसूचना पोर्टल** बनाया गया है। इस पोर्टल पर 27 विभागों की 51 योजनाओं/सेवाओं की 144 प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवायी जा रही हैं। बेहद कम समय में ही लगभग 8 लाख 30 हजार विजिटर्स द्वारा विभिन्न सेवाओं की लगभग 50 लाख सूचनायें प्राप्त की जा चुकी हैं। इसी दिशा में, अब सरकार अन्य विभागों एवं उनकी योजनाओं/सेवाओं को जनसूचना पोर्टल पर लायेगी।
- 20 अगस्त, 2019 को भारत रत्न राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर जयपुर में I.T. आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से आये बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के उत्साह को देखते हुए हमने तय किया है कि स्टार्टअप्स के विकास के लिए **75 करोड़ रुपये** के **'राजीव** @75 फण्ड' की स्थापना की जायेगी। राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं (जैसे आईआईटी-जोधपुर, बिट्स-पिलानी, एमएनआईटी-जयपुर, एम्स- जोधपुर आदि) सहित अन्य संस्थानों में स्थापित incubators को i-Start राजस्थान से जोड़ा जायेगा।
- इस वित्त वर्ष में Ease of Doing Business (EoDB) के तहत ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS) को प्रदेश के

कौशल एवं रोजगार

Rajiv Gandhi Digital Skill Program के तहत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा युवाओं के लिए राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय (RISU) के सहयोग से emerging new digital technologies जैसे कि Artifical Intelligence, Big Data Analytics एवं Robotics इत्यादि में On-line Digital Skills के कोर्सेज शुरू किये जायेंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण सहित 14 विकास न्यासों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। अब इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी नगर निकायों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

- सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधीजी की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को **'राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब-राजगृह'** (RAJGRIH) के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं की प्रदायगी को और मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया है।
- Artificial Intelligence के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु प्रदेश में एक Artificial Intelligence Lab की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से नवयुवकों को इस तकनीक में उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- गत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप भामाशाह की जगह **राजस्थान जन-आधार योजना** सफलतापूर्वक प्रारम्भ की जा चुकी है। अब तक लगभग 1 करोड़ 75 लाख परिवार एवं 6 करोड़ 50 लाख व्यक्ति इस पर नामांकित किये जा चुके हैं। जन-आधार कार्ड का उपयोग 39 योजनाओं में प्रारंभ हो चुका है। अब, आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ, जन-आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

कला एवं संस्कृति

- हमारे पिछले कार्यकाल में राज्य में नागरिकों की उल्लेखनीय सेवा एवं गुणों को ध्यान में रखते हुए **राजस्थान रत्न पुरस्कार** से सम्मानित किये जाने की योजना लागू की गई थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। अब मैं, इस योजना को पुन: लागू करने की घोषणा करता हूँ।
- प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर, झुंझुनूं, जैसलमेर, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर के 22 स्मारकों का पुनरूद्धार करवाया जायेगा। इसके लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर सहित जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व अलवर कार्यालयों में उपलब्ध लगभग 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों का digitization तथा microfilming कर उन्हें ऑनलाइन किया जायेगा, जिससे देश-विदेश के शोधार्थी व आमजन अभिलेखों का आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन (टाउन हॉल) जोधपुर शहर का एकमात्र प्रेक्षागृह है, जिसके जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

वन एवं पर्यावरण

- प्रदूषण की दृष्टि से देश के कई शहर खतरे की सीमा पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जो हम सभी के लिए एक चुनौती है। राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनभागीदारी से सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाये जायेंगे।
- गुरुनानक देव जी की 550वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान/नये उद्यान को **गुरुनानक जयन्ती पार्क** के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपये का व्यय होगा।
- राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने और इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु **'राजस्थान राज्य वन विकास निगम'** गठित किया जायेगा।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले की 'जिला पर्यावरण योजना' तथा राज्य के लिए 'राज्य पर्यावरण योजना' बनायी जायेगी। इस पर वर्ष 2020-21 में 3 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय होंगे। खेजड़ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान करने वाली **अमृता देवी** को समर्पित 10 लाख रुपये की लागत से एक **शहीद स्मारक** का निर्माण किया जायेगा।

वन एवं पर्यावरण

गुरुनानक देव जी की 550वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान/नये उद्यान को **गुरुनानक जयन्ती पार्क** के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपये का व्यय होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त जिला रसद कार्यालयों, खाद्य विभाग मुख्यालय एवं राजकीय गोदामों का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा। इस हेतु लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए उचित मूल्य दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने हेतु अधिकृत किया जायेगा।

सहायता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा

- आगामी वर्ष में नागरिक सुरक्षा एवं State Disaster Response Force की क्षमता संवर्धन हेतु 10-10 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन विभाग को बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु 12 करोड़ रुपये के उपकरण एवं वन विभाग को जंगलों में लगने वाली आग को तत्काल नियंत्रित करने हेतु लगभग 3 करोड़ रुपये के अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही, प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी हेतु समस्त जिला कलक्टर्स को ड्रोन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।
- आगजनी की घटनाओं पर रोकथाम हेतु 26 करोड़ रुपये की लागत के उच्च क्षमता वाले 100 अग्निशमन वाहन (Fire Tenders) जिलों में उपलब्ध करवाये जायेंगे। इनके संचालन हेतु 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

गृह

- जैसा कि विदित है सरकार ने थाने में प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में FIR दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है। थानों में प्राप्त समस्त परिवादों को CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and System) पर online दर्ज करवाने की भी व्यवस्था कर दी गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान, देशभर में पहला राज्य है। गत वर्ष हमारे द्वारा की गई घोषणा के क्रम में अब तक 486 पुलिस थानों में स्वागत कक्षों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं एवं कार्य प्रगति पर है।
- पुलिस को संसाधनों से लैस करने के लिए 70 करोड़ रुपये के 1 हजार 682 नवीन वाहन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
- राज्य में ERSS (Emergency Response Support System) चरणबद्ध रूप से स्थापित करने की घोषणा हमने गत बजट में की थी, ताकि आपात स्थिति में 108 की तर्ज पर 112 नम्बर डायल करने पर एक निश्चित अल्पावधि में मोबाइल पुलिस यूनिट घटनास्थल पर पहुंच सके। इसी क्रम में इस वर्ष यह व्यवस्था पायलट बेसिस पर अलवर तथा भरतपुर जिले में प्रारंभ की जा रही है। आगामी वर्ष में योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- प्रदेश में पनप रहे विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोहों के विरूद्ध राज्य की पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान को सुदृढ़ करने के लिए SOG में दो नई फील्ड यूनिट्स स्वीकृत की जायेंगी। साथ ही, मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए SOG में एक नई एंटी नारकोटिक यूनिट का गठन किया जायेगा।
- पश्चिमी राजस्थान में विकसित हो रही रिफाइनरी, तेल उत्पादन, सौर और पवन ऊर्जा एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के लिए बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर के पुलिस थानों को अतिरिक्त मोबाइल यूनिट मुहैया करवायी जायेगी और चिन्हित थानों को क्रमोन्नत तथा पुलिस चौकियों को सुदृढ़ किया जायेगा।
- वर्तमान में राज्य में केवल जयपुर में DNA Test की सुविधा उपलब्ध है। आपराधिक प्रकरणों में DNA Test के महत्त्व को देखते हुए प्रथम चरण में क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला, जोधपुर में तथा द्वितीय चरण में क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला, अजमेर में DNA खंड प्रारंभ किया जायेगा।

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

- राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल-निवास, आय, विवाह आदि प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस- रिन्यूवल, पेयजल कनेक्शन, पेंशन पीपीओ आदि हेतु नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराने पर, इनकी **door step डिलीवरी** के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई जायेगी।
- जयपुर एयरपोर्ट पर स्टेट फ्लाईंग स्कूल (क्लब) पुन: प्रारंभ किया जायेगा।
- प्रदेश के 6 जिलों के **जिला गजेटियर्स** का लेखन/अद्यतन का कार्य प्रगति पर है। शेष जिलों के जिला गजेटियर्स को अद्यतन करने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में हाथ में लिया जायेगा।

राजस्व एवं सैनिक कल्याण

- आगामी वित्तीय वर्ष में उपखंड, तहसील, उप-तहसील कार्यालयों एवं आवासों के कुल 35 भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
- राज्य में 294 उपखण्ड कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक उपखण्ड कार्यालय में आवश्यकतानुसार 1 कनिष्ठ सहायक एवं 1 सूचना सहायक का पद सृजित किया जायेगा। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा।
- राज्य सरकार द्वारा **कृषि ऋण रहन पोर्टल** बनाया गया है, जिसके माध्यम से किसान कृषि ऋण हेतु किसी भी बैंक में आवेदन कर सकेगा। संपूर्ण प्रदेश में इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से लागू कर

रहन नामांतरण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पेपरलेस की जायेगी।

- राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सर्वे उपकरण के माध्यम से सीमाज्ञान तथा भू-प्रबन्ध कार्य करवाये जाने हेतु 12 आधुनिक सर्वे उपकरण (DGPS) उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- प्रदेश के 24 जिला सैनिक कार्यालयों में आगन्तुक पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारजनों हेतु सुविधायें विकसित करने के लिए राशि 5 लाख रुपये प्रति जिले की दर से जिला सैनिक कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के 14 जिलों दौसा, झालावाड़, धौलपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही, बारां, बीकानेर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बूंदी, टोंक एवं करौली में शहीद स्मारक बने हुए नहीं है। इन सभी स्थानों पर एकरूपता को ध्यान में रखते हुए राशि 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से **शहीद स्मारकों** का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

देवस्थान

- जैसा कि विदित है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2019 में इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रदेश से समानुपातिक भागीदारी के रूप में हर क्षेत्रा से वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया जाये, साथ ही अगले वर्ष इस योजना का विस्तार भी प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन

- राज्य में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रथम चरण में आगामी वर्ष 48 नये कोर्ट खोले जायेंगे। इनमें सीनियर CJ and ACJM कोर्ट बानसूर (अलवर), रायपुर (भीलवाड़ा), टोडाभीम (करौली) तथा ACJM कोर्ट अटरू (बारां), देसूरी (पाली) बिलाड़ा (जोधपुर) एवं ACJ and JM कोर्ट नाथद्वारा (राजसमन्द) शामिल हैं। साथ ही, CJ and JM कोर्ट नावां को सीनियर CJ and ACJM कोर्ट में क्रमोन्नत किया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण

- राज्य का प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी शासन व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। मैं जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूँ।
- जैसाकि विदित है कि हमारे द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में अब तक 34 हजार 682 नई नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं 82 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में आने वाले वर्ष में नियमानुसार भर्तियां की जायेंगी। इससे एक ओर जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उक्त भर्ती प्रक्रिया को सतत रखते हुए वर्ष 2020-21 में लगभग 53 हजार पदों पर भर्तियां की जायेंगी:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल पद
1	Medical & Health	4,369
2	Medical Education	573
3	Co-operative	1,000
4	Education	41,000
5	Local Self Govt.	1,039
6	Home	5,000
7	GAD	200
	Total	**53,181**

अध्यक्ष महोदय,

- विधानसभा के माननीय सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास को लेकर समस्या बनी रहती है। इसके उचित समाधान की दृष्टि से जालूपुरा स्थित विधायक आवास परिसर का नियमानुसार निष्पादन करके, विधानसभा परिसर के समीप बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- गत वर्ष हमारे द्वारा नवीन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सिलिकोसिस एवं MSME सम्बन्धी नीतियां जारी की गई। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में बालिकाओं तथा महिलाओं के समग्र विकास हेतु **महिला कल्याण नीति**, कृषकों के उत्थान हेतु राजस्थान **FPO** (Farmer Producer Organization) **नीति**, शिल्प कला के विकास हेतु **हस्तशिल्प नीति** एवं स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए **स्टार्ट-अप नीति** लागू की जायेगी।
- हमारे प्रदेशवासियों के आने वाले कल के लिए मैंने विस्तार से अपनी कार्ययोजना सदन के सम्मुख रखी है। हमारा कल सुनहरा हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरे समर्पण से जुटी हुई है। प्रदेश के विकास के जो सात संकल्प इस बजट में हमने तय किये हैं, वही आगामी वर्ष के लिए हमारा प्रमुख एजेंडा होगा। मेरी प्रतिबद्धता सदैव शासन की जवाबदेही और सेवाओं की प्रभावी व समयबद्ध अदायगी पर रही है। हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे।
- मैं वर्तमान की चुनौतियां समझता हूँ और आप सभी के सहयोग से इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहता हूं।

जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
अपने इरादों का इम्तिहां अभी बाकी है,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं,
आगे अभी सारा आसमां बाकी है। •

कर प्रस्ताव

- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना, सम्पत्ति के बाजार मूल्य (DLC) के स्थान पर, पट्टों पर वसूल की गई राशि पर किये जाने की घोषणा करता हूँ।
- MSME एक्ट 2019 की सफलता के क्रम को आगे बढ़ाते हुये मैं, Sick (बीमार) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट व पंजीयन शुल्क में रियायत देने तथा ऐसे उद्योगों के नीलामी में विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर किये जाने की घोषणा करता हूँ।
- राज्य में निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र; नीमराना, भिवाड़ी, अलवर आदि की भूमियों, विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की DLC दरों में वर्षो से व्याप्त विसंगतियों को दूर कर रियल एस्टेट में निवेश व उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- वर्षो से लम्बित स्टाम्प प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की जायेगी, जिसके तहत 30 जून, 2020 तक बकाया स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की शत-प्रतिशत छूट देने की घोषणा करता हूँ।
- प्रदेश में उद्योगों को सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने एवं रियल एस्टेट क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए भूमि की वर्तमान DLC दरों को 10 प्रतिशत घटाकर स्टाम्प ड्यूटी की दर को 1 प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 में भी DLC दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी।
- राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के पोर्टल पर ऑनलाइन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SHCIL) के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

- स्टाम्प ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक माह तथा राजस्थान से बाहर निष्पादित लेकिन राज्य में स्थित सम्पत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की जायेगी।
- वर्तमान में प्रचलित भूमिकर (Land Tax) से संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण किया जायेगा तथा भूमिकर की दरों को तर्कसंगत करते हुए इसके भुगतान की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जायेगा।
- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एक मुश्त अग्रिम स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में हाल ही में किये गये संशोधन से Securities Instruments पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर व राज्यों में वितरण की व्यवस्था तय की गई है। इस प्रकार के प्रावधान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में भी किए जायेंगे।
- दस्तावेज की वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना (Evasion) करने के मामलों में कलक्टर (स्टाम्प) को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की जायेंगी।

वाणिज्यिक कर विभाग

- GST लागू होने पर आ रही अड़चनों को दूर करने व व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जायेगा तथा जीएसटी Audit एवं Anti-Evasion कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त विभाग में ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जायेगा।
- प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए राजस्थान जी. एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के पदनाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष करने एवं तदनुरूप सेवा नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।
- जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर Radio Frequency Identification Device **(RFID)** व Automatic Number Plate Recognition **(ANPR)** नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

उपनिवेशन विभाग

- हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी रही है, अत: मैं, उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, इन क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक, इस तिथि तक की समस्त बकाया किश्तें जमा कराये जाने पर (i) ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किया जाना एवं (ii) बाकी बची हुई किश्तें भी एकमुश्त जमा कराये जाने पर उपर्युक्त ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

नगरीय विकास, आवासन व राजस्व विभाग

- 'निरोगी राजस्थान' मेरी सरकार की प्राथमिकता है। खेल इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। अत: मैं, स्टेडियम, खेल मैदान एवं क्रीड़ा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिये, कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

परिवहन विभाग

- औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संविदा यान के रूप में संचालित बसों के लिये मोटर वाहन कर को दो श्रेणियों में विभक्त कर बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर की राशि अधिकतम 14 हजार रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य की दो नगर पालिकाओं, जिनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक नहीं है, उनमें संचालित 32 बैठक क्षमता वाले स्टेज कैरिज वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर की दर 250 रूपये के स्थान पर 100 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में बिना परमिट अवैध रूप से संचालित होने वाले निजी यात्री वाहनों पर एक वित्तीय वर्ष के लिए देय मोटर वाहन कर को, उस वाहन के लिए देय एक बारीय कर का 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- वाहन कर में सरलीकरण के उद्देश्य से Construction Equipment Vehicle एवं Vehicle Fitted with Equipment पर लगने वाले कर को एक समान करते हुये इनके चैसिस के रूप में क्रय किये जाने पर कर की दर कीमत के 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत एवं पूर्णतया निर्मित वाहनों पर 7 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में संचालित संविदा बसों पर मोटर वाहन कर में राहत देते हुये 23 सीटर से लेकर 40 से अधिक सीटर बसों की तीनों श्रेणियों पर 100 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह की छूट दिये जाने की घोषणा करता हूँ।
- उप.नगरीय मार्गों पर वर्तमान में देय प्रतिदिन संचालित दूरी आधारित मोटर वाहन कर में राहत प्रदान करते हुये निर्धारित चारों

श्रेणियों में 50 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह छूट देने की घोषणा करता हूँ।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- खनिज अन्वेषण को गति देने के लिये State Mining Exploration Trust (राज्य खनिज अन्वेषण न्यास) का गठन किया जायेगा। राज्य में निकलने वाले खनिज एवं रॉयल्टी की गणना व Evasion को रोकने के लिये IT व ड्रोन सहित अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जायेगा।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

- आजकल मानहानि (Defamation) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में ऐसे मामलों में दावे की रकम के आधार पर (Ad-Voleram) कोर्ट फीस लगती है जो बहुत ज्यादा होती है। इससे कई लोग दावा ही नहीं कर पाते हैं अत: मानहानि के मामलों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कोर्ट फीस की अधिकतम सीमा को 25000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
- **इस प्रकार उपरोक्तकर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है** तथा इन कर प्रस्तावों से लगभग 130 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की गई है।
- इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।
- इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

संशोधित अनुमान वर्ष 2019–20 एवं बजट अनुमान वर्ष 2020-21 :

- मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के अन्तरिम बजट में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 46 हजार 411 करोड़ 8 लाख रुपये देने का अनुमान किया था, जिसे वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों में घटाकर 44 हजार 461 करोड़ 86 लाख रुपये कर दिया। वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों में इसे और घटाते हुए मात्रा 36 हजार 49 करोड़ 14 लाख रुपये कर दिया गया है।
- इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों में वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट की तुलना में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में 10 हजार 361 करोड़ 94 लाख रुपये की कटौती की गई है।
- अब मैं, वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियाँ 1 लाख 56 हजार 715 करोड़ 56 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय 1 लाख 84 हजार 756 करोड़ 60 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा 28 हजार 41 करोड़ 4 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 68 हजार 135 करोड़ 52 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय 40 हजार 72 करोड़ 31 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य 28 हजार 63 करोड़ 21 लाख रुपये

- वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियाँ 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ 42 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय 1 लाख 85 हजार 750 करोड़ 3 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ 52 हजार 360 करोड़ 25 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय 39 हजार 981 करोड़ 47 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य 12 हजार 378 करोड़ 78 लाख रुपये

राजस्व घाटा

- राज्य को केन्द्रीय करों में मिलने वाली हिस्सा राशि सहित राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षित वृद्धि संभावित नहीं है तथा सरकार के कार्यकलापों के संचालन व लोक कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना आवश्यक है, इस कारण वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा

- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 33 हजार 922 करोड़ 77 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 2.99 प्रतिशत है।
- मैं, वर्ष 2020-21 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
- वर्ष 2020-21 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट-पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं।
- इन्हीं भावनाओं के साथ मैं, बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

:: जयहिन्द ::

बजट बहस पर जवाब में मुख्यमंत्री ने की महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

चिकित्सा अधिकारियों के 2 हजार नए पद सृजित होंगे
परवन परियोजना में वर्ष 2020-21 के लिए 866 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट 2020-21 पर चर्चा के बाद अपने वक्तव्य में निम्न घोषणाएं कीं :-

- प्रदेश में बामणवास-सवाईमाधोपुर, लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर एवं उच्चैन- भरतपुर में नगरपालिकाओं का गठन किया जायेगा।
- राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा में CCU व ICU खोले जायेंगे।
- राजकीय चिकित्सालय, हिन्डौन सिटी में 50 बेड की बढ़ोतरी की जायेगी।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैपऊ में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड किए जाएंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड किए जाएंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा में 50 बेड की बढ़ोतरी की जायेगी।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुरा-जयपुर में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड किए जाएंगे।
- सीकरी-भरतपुर, टिब्बी-हनुमानगढ़, सुल्तानपुर-कोटा, खतौली-कोटा, मांगरोल-बारां, कवाई-बारां, कापरेन-बूंदी, पिलानी-झुंझुनूं एवं लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर में स्वतंत्र मंडी बनायी जायेंगी।
- सिरोही जिले के तीन कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज एवं पिंडवाड़ा तथा 33 गांवों और 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला बांध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की DPR बनायी जायेगी।
- राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोला जायेगा।
- राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ में नवीन विषय समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान खोला जायेगा।
- राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) में भूगोल व हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जायेंगी।
- मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जायेगा।
- पंचायत समिति अराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय और हिंगोटा, रसीदपुर, बालाहेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय खोले जायेंगे।
- फागी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।
- पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- चाकसू-जयपुर एवं नदबई-भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाएंगे।
- ब्रजपुरा किशनपुरा-जयपुर, ग्राम पंचायत बागथर बसेड़ी-धौलपुर, अयानी उपखंड ईटावा-कोटा में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जायेंगे।
- इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गयी है। उक्त घोषणा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के 2000 नये पद सृजित किये जायेंगे।
- राज्य के दो जिलों-जयपुर एवं जोधपुर के परकोटे के क्षेत्र के लिए बाइक एम्बुलेंस (Bike ambulance) हेतु पायलट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा।
- राज्य के संभाग मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की जायेगी।
- राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जायेगी।
- भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी।
- जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
- जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
- जल योजना राजगढ़ जिला चूरू में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दवाब से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 46 करोड़ 85 लाख रुपये की पुनर्गठन योजना बनाई गई है। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
- बीकानेर जिले की तहसील नोखा व बीकानेर के कुल 146 गांवों व 2 शहर (नोखा व देशनोक) को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की नई डीपीआर बनाई जायेगी।
- परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। वर्ष 2020-21 हेतु 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति लाई जायेगी। •

भंवर म्हाने खेलण दो गणगौर...

आलेख– पूनम मेहता
छायाचित्र : राकेश शर्मा 'राजदीप'

गणगौर पर्व सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं धार्मिक चेतना की ज्योति किरण है। अंतहीन पवित्र दांपत्य जीवन की खुशहाली से जुड़ा यह ऐसा पर्व है जिसमें गणगौर के रूप में गौरी-पूजन एक अनूठा अनुष्ठान किया जाता है। कुवांरी और विवाहिताएं समान रूप से इस पर्व को मनाती हैं। विवाहिताएं वर की दीर्घायु की व गृहस्थ सुख की और कुंवारी कन्याएं इच्छित वर प्राप्ति का वर मांगती है। राजस्थान के लोकमानस में, लोकांचलों में गौरी-पूजन का पर्व बसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। असल में गणगौर पर्व के समूचे स्वरूप में शिव और पार्वती की पौराणिक महिमा को लौकिक संदर्भ मिला हुआ है। यहां शिव प्रलयंकर नहीं बल्कि गणगौर पूजने वाली नवोढ़ाओं और कुमारियों के एक सहृदय रिश्तेदार के रूप में होते हैं जिनसे वे ठिठोली भी कर सकती है। गौर अथवा गवर पूजा सखी-भाव से की जाती है। नवौढ़ा अपने पति से एक गीत में कहती भी है, 'भंवर म्हाने खेलण दो गणगौर...।'

होली दहन के दूसरे दिन से ही होली की राख, गोबर व काली मिट्टी से गणगौर बनाई जाती है। कहीं-कहीं आठ पिंडी राख व आठ पिंडी गोबर की गणगौर बनाकर डलियां मे दूब पर रख दी जाती है। आजकल शहरों में बने-बनाये गणगौर-ईसर भी मिलते हैं, जिन्हें गणगौर के दिन वस्त्राभूषण धारण करवाये जाते हैं और विधिपूर्वक रोली, काजल व मेहंदी की 16-16 बिंदिया सजाकर पूजा जाता है। पूजन में हरी घास की कोंपलें, पुष्प, कनेर के पत्ते इत्यादि काम आते हैं। 16 बार किए गए पूजन में प्रत्येक बार हरी दूब अर्पण की जाती है।

ग्रामीण अंचलों में कुवांरी व नव विवाहिताएं कुओं-तालाबों का जल कलश में भर कर गणगौर पूजन को जाती हैं। एक के ऊपर एक रखे ये कलश फूल और हरी दूब से अटे होते हैं। गौर-ईसर को शिव और पार्वती की जोड़ी ही माना जाता है। गणगौर पर्व कुटम्ब भावना का एक तरह से रूपक है। राजस्थान के विभिन्न नगरों में गणगौर की शाही सवारी निकलती है। मेवाड़ की गणगौर अत्यन्त प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ला द्वितीय को गणगौर का 'सिंझारा' धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह उदयपुर में

वैशाख कृष्णा तृतीया को 'धींगारू' गणगौर का त्योंहार मनाया जाता है। उदयपुर में महाराजा राजसिंह प्रथम ने अपनी महारानी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरूद्ध जबरदस्ती त्योंहार प्रचलित किया। इसी कारण इसका नाम 'धींगा गणगौर' प्रसिद्ध हुआ। उदयपुर के अलावा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर आदि में भी गणगौर की शाही सवारियां निकलती है। ईसर की पूजा शिव रूप में की जाती है। कुमारी कन्याएं ईसर जैसा पति चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव-पार्वती की जोड़ी हो। गणगौर का पर्व पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं लोक आस्था का पावन प्रतीक है। यह ऐसा रसवन्ती त्योंहार है जिसमें ईसर और गवरा के दाम्पत्य-रस के बहाने गणगौर पूजने वाली कुमारिकाएं अपने मन को स्त्री-पुरूष के बीच के चिर आकर्षण से सहज शिक्षित करती है। •

फार्म–1
(नियम 3 देखिये)

1. समाचार पत्रिका का नाम	:	राजस्थान सुजस
2. समाचार पत्रिका की भाषा	:	हिन्दी
3. प्रकाशन का स्थान	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
4. प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
5. मुद्रक का नाम	:	महेन्द्र सोनी
क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
पता प्रेस	:	प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस 12, मित्र नगर, हवा सड़क, रामनगर, सोडाला, जयपुर
6. प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र सोनी
क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सचिवालय, जयपुर
7. सम्पादक का नाम	:	डॉ. राजेश कुमार व्यास
क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सचिवालय, जयपुर

8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों। मैं, महेन्द्र सोनी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

महेन्द्र सोनी

मुख्यमंत्री ने किया होली पूजन
प्रदेश में खुशहाली की कामना की

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर होली पूजन किया तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ आरती की तथा उसके बाद होली पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच होलिका दहन किया। होलिका दहन के दौरान राजस्थान पुलिस की 4 आरएसी बटालियन के

के अनेक गणमान्यजन एवं राज्य सरकार के अधिकारी भी सपरिवार उपस्थित थे।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

पूर्व विधान सभा भवन (सवाई मानसिंह टाउन हॉल)

धरोहर

राजस्थान विधान सभा में पहली बार 7 अप्रेल, 1952 को वर्ष 1952-53 का आय-व्ययक (बजट) तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा प्रस्तुत किया गया। राज्य के विधायी कार्यों के साक्षी रहे सवाई मानसिंह टाउन हॉल (पूर्व विधान सभा भवन) में 30 मार्च, 2000 को वित्त मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह ने राज्य का अंतिम बजट भाषण दिया। लालकोठी स्थित नवीन विधान सभा भवन में ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र से बैठकें आरम्भ हुई। यहां 27 मार्च, 2001 को प्रातः 12.42 बजे सदन की पहली बैठक आरम्भ हुई। नवीन भवन में प्रथम बजट भाषण देने वाले भी श्री प्रद्युम्न सिंह ही थे। श्री सिंह ने 29 मार्च, 2001 को नवीन भवन में पहला बजट भाषण दिया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 20 फरवरी 2020 को दिए गये बजट भाषण को मिलाकर अब तक कुल 78 बजट भाषण विधान सभा में दिये जा चुके हैं। इनमें से 54 भाषण सवाई मानसिंह टाउन हॉल (पूर्व विधान सभा भवन) में दिये गये तथा शेष 24 बजट भाषण इस वर्तमान विधान सभा भवन में दिये गये है।

आलेख : विनोद कुमार मिश्रा
छाया सौजन्य : राजस्थान विधान सभा

प्रकाशक व मुद्रक–सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, महेन्द्र सोनी द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक– डॉ. राजेश कुमार व्यास • मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, 12, मित्र नगर, हवा सड़क, रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 1,00000 प्रतियां